प्रधानमंत्री 28 नवंबर को कर्नाटक और गोवा जाएंगे

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

लोक शक्ति

(हांगकांग) बड़ा हादसा : आठ मंजिला इमारत में लगी भीषण आग, 44 की मौत; 279 लोग अब भी लापता

RNI Regn. No.7789/1964 | वर्ष-61 > अंक - 328 | रायपुर | शुक्रवार 28 नवंबर 2025 विक्रम संवत 2082 | पृष्ठ 8 > मूल्य : 2 रू. | डाक पंजीयन : C.G/RYP DN/71/2023-25

भारत शांति के लिए कठोर लेकिन जिम्मेदार कार्रवाई करने की नैतिक स्पष्टता रखता है : राष्ट्रपति

नई दिल्ली एजेंसी।

भारत की काउंटर-टेररिज्म और डिटरेंस रणनीति ने दुनिया को न केवल भारत की सैन्य क्षमता दिखाई है, बल्कि यह भी बताया है कि भारत शांति के लिए कठोर लेकिन जिम्मेदार कार्रवाई करने की नैतिक स्पष्टता रखता है। यह बात गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कही। वह भारतीय सेना के चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2025 के उद्घाटन समारोह में बोल रही थीं। राष्ट्रपति ने सीमावर्ती क्षेत्रों में अवसंरचना, कनेक्टिविटी और शिक्षा को मजबूत करने में सेना के योगदान की सराहना की। उन्होंने यहां देश की सुरक्षा, सैन्य सुधारों व भविष्य की रणनीतिक दिशा पर महत्वपूर्ण संबोधन दिया। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय रक्षा तंत्र केवल सीमाओं की सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय विकास का भी प्रमुख स्तंभ है। उन्होंने बदलते वैश्विक परिदृश्य पर कहा कि आज की दुनिया तकनीकी बदलावों, उभरते शक्ति केंद्रों, साइबर स्पेस व कॉग्निटिव वॉर जैसे नए युद्ध क्षेत्रों और बदलते गठबंधनों से गुजर रही है। ऐसे समय में भारत अपने सांस्कृतिक सिद्धांत 'वसुधैव कुटुम्बकम' के आधार पर सामरिक स्वायत्तता और वैश्विक जिम्मेदारी दोनों का संतुलन बनाए हुए है।

पंजाब : अमृतसर में पाकिस्तानी हैंडलर से जुड़े दो तस्कर गिरफ्तार, आईईडी बरामद

अमृतसर एजेंसी

पंजाब पुलिस ने सीमा पार से चल रहे खतरनाक स्मगलिंग व आतंकी मॉड्यूल को करारा झटका दिया है। खुफिया सूचना के आधार पर अमृतसर रूरल पुलिस ने बुधवार तड़के विशेष अभियान चलाकर दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया और उनके पास से एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) और दो मोबाइल फोन बरामद किए। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से यह जानकारी साझा करते हुए लिखा, इंटेलिजेंस आधारित ऑपरेशन में अमृतसर रूरल पुलिस ने क्रॉस-बॉर्डर स्मगलिंग मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया। इस मामले में दो आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। इस दौरान एक आईईडी और दो मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। शुरुआती जांच में पाकिस्तान स्थित हैंडलर से संपर्क का पता चला है। पंजाब पुलिस सीमा-पार के अपराध को खत्म करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पुलिस सूत्रों के अनुसार गिरफ्तार आरोपी अमृतसर के सीमावर्ती गांव के रहने वाले हैं और लंबे समय से ड्रोन के जरिए हथियार व नशीले पदार्थों की खेप पाकिस्तान से ले रहे थे।

पीएम मोदी बोले- भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र बदल रहा

स्काईरूट के इनफिनिटी कैंपस का उद्घाटन

एजेंसी

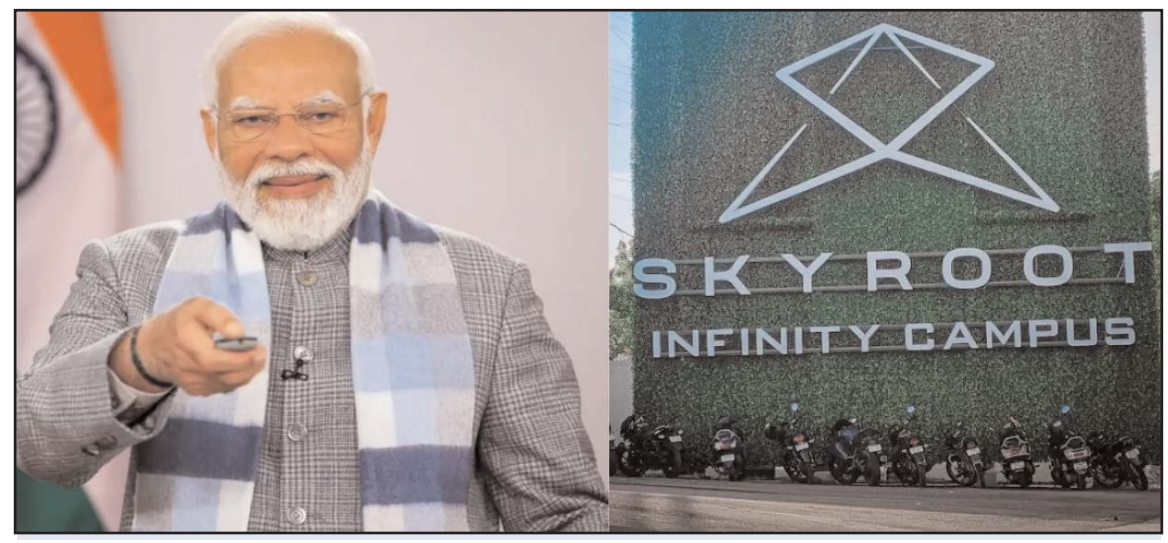

नई दिल्ली ,प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को भारतीय स्पेस स्टार्टअप स्काईरूट के इनफिनिटी कैंपस का उद्घाटन किया। साथ ही इसके पहले उन्होंने ऑर्बिटल रॉकेट, विक्रम-द्ध को भी दिखाया। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि देश स्पेस सेक्टर में एक ऐसा मौका देख रहा है, जो पहले कभी नहीं मिला। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आज, निजी क्षेत्र भारत के स्पेस इकोसिस्टम में एक बड़ी छलांग लगा रहा है। स्काईरूट का इनफिनिटी कैंपस भारत की नई सोच, इनोवेशन और युवा शक्ति की झलक है।

उन्होंने कहा कि भरोसे, क्षमता और वैल्यू के साथ भारतीय स्पेस टैलेंट ने पूरी दुनिया में एक मजबूत पहचान बनाई है। पीएम मोदी ने कहा कि देश की अंतरिक्ष यात्रा बहुत कम संसाधन के साथ शुरू हुई थी, लेकिन हमारी उम्मीदें कभी सीमित नहीं थीं। उन्होंने कहा कि साइकिल पर ले जाए जाने वाले रॉकेट के एक हिस्से से, आज भारत ने दुनिया के सबसे भरोसेमंद लॉन्च व्हीकल में से एक बनाने वाले के तौर पर अपनी जगह बनाई है।

पीएम मोदी ने कहा, देश ने साबित कर दिया है कि हमारे सपनों की ऊंचाई रिसोर्स से नहीं, बल्कि पक्के इरादे से तय होती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि देश के पास स्पेस सेक्टर में ऐसी काबिलियत है जो दुनिया के कुछ ही देशों के पास है। हमारे पास एक्सपर्ट इंजीनियर, हाई-क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, वर्ल्ड-क्लास लॉन्च साइट्स और इनोवेशन को बढ़ावा देने वाली सोच है।

उन्होंने इस सफलता का क्रेडिट पिछले दशक में भारत के स्पेस सेक्टर में किए गए ऐतिहासिक सुधारों को भी दिया। प्रधानमंत्री ने कहा, सरकार ने इस सेक्टर को निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया है, ताकि स्टार्टअप और उद्योग हमारे साइंटिफिक इकोसिस्टम के साथ मिलकर काम कर सकें। पिछले छह से सात सालों में भारत ने अपने स्पेस सेक्टर को एक खुले, सहकारी और इनोवेशन-ड्रिवन डोमेन में बदल दिया है। यह तरक्की आज के प्रोग्राम में साफ तौर पर दिखती है। उन्होंने आगे कहा, ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर तेजी से एक आकर्षक जगह बनता जा रहा है। दुनिया भर में छोटे सैटेलाइट्स की मांग लगातार बढ़ रही है और स्पेस को अब एक स्ट्रेटेजिक एसेट के तौर पर पहचाना जा रहा है। आने वाले सालों में ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी कई गुना बढ़ने वाली है। यह भारत के युवाओं के लिए एक बड़ा मौका है। इस बीच, स्काईरूट का इनफिनिटी कैंपस एक स्टेट-ऑफ-द-आर्ट फैसिलिटी है और इसमें कई लॉन्च व्हीकल को डिजाइन करने, डेवलप करने, इंटीग्रेट करने और टेस्ट करने के लिए लगभग 200,000 स्क्वायर फीट का वर्कस्पेस होगा, जिसमें हर महीने एक ऑर्बिटल रॉकेट बनाने की कैपेसिटी होगी। प्रधानमंत्री ने स्काईरूट के संस्थापक पवन चंदना और भरत ढाका की भी तारीफ की, जो दोनों इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के एल्युम्नाई और इसरो के पूर्व वैज्ञानिक हैं।

बंगाल में बाबरी मस्जिद के ऐलान के बीच गीता पाठ सह शौर्य दिवस की तैयारी

कोलकाता एजेंसी।

बंगाल में ममता सरकार के लिए छह दिसंबर सिर दर्द बन सकता है। वैसे भी इस दिन बंगाल में राज्य सरकार अलर्ट रहती है लेकिन इस साल को मुर्शिदाबाद में कथित व प्रस्तावित बाबरी मस्जिद के नींव स्थापित करने के ऐलान के कारण पश्चिम बंगाल का राजनीतिक तापमान अचानक तेजी से बढ़ गया है। एक तरफ टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर की बाबरी मस्जिद निर्माण से जुड़ी घोषणा पर विवाद गहराता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ गीता जयंती को लेकर सनातन संगठनों की तैयारी तेज हो गई है। इन दोनों घटनाओं के साथ उसी दिन टीएमसी की बड़ी राजनीतिक रैली भी होनी है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि, तमाम सनातनी संगठनों के द्वारा इस दिन कई धार्मिक आयोजन होंगे व कई संगठन इसे शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं। वैसे टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने ही कुछ दिन पहले बयान दिया था-

पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं 83 हजार से घटकर 5 हजार हुईं : शिवराज सिंह

किसानों को सम्मिलित करते हुए चिंतन बैठक करेंगे, 5 साल की कृषि योजनाएं बनाएंगे- श्री चौहान

केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा; रणसिंह कलां गावं को मॉडल के रूप में पूरे देश में प्रस्तुत किया जाएगा

प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पंजाब के विकास के लिए करेंगे हरसंभव प्रयास- श्री शिवराज सिंह

पीआईबी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान आज एक दिवसीय पंजाब दौरे पर हैं। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने मोगा के रणसिंह कलां गांव के किसान भाई-बहनों,ग्रामवासियों और हितधारकों से मुलाकत कर विगत 6 वर्षों से पराली ना जलाने और पराली के उचित प्रबंधन में अभूतपर्व उपलब्धि के लिए सभी की सराहना की और बधाई दी। मुख्य आयोजन के पहले केंद्रीय मंत्री ने मीडिया से भी बात की और बताया कि पराली जलाने की घटनाओं ने पूरे देश को चिंतित किया था। पराली जलने के कारण खेत तो साफ हो जाता था, लेकिन मित्र कीट भी जल जाते थे। साथ ही पराली जलाने से प्रदूषण की समस्या भी पैदा होती थी।÷ केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ÷मैं आज पंजाब को बधाई देने आया हूं। पंजाब के पराली प्रबंधन के प्रयोग को सारे देश में ले जाने आया हूं। पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में इस साल 83 प्रतिशत की कमी आई है। जहां लगभग 83 हजार पराली जलाने की घटनाएं होती थी वह अब घटकर 5 हजार के करीब हो चुकी हैं।÷ आगे, केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि ÷किसान भाई-बहन पूछते हैं कि पराली ना जलाएं तो विकल्प क्या है? गेहूं और अन्य फसल की बुवाई के लिए खेत साफकैसे करें? इन सवालों के समाधानों के लिए रणसिंह कलां गांव में प्रयोग हुए हैं। रणसिंह कलां गावं ने उदाहरण पेश किया है। यहां पिछले 6 वर्षों से पराली नहीं जलाई गई है, यहां किसान भाई-बहन सीधे पराली को खेत में मिलाते हैं और डायरेक्ट सीडिंग करते हैं।÷

दिल्ली-एनसीआर में सांस लेना हुआ मुश्किल, हवा हुई 'बेहद खराब', कई इलाकों में एक्यूआई 350 के पार पहुंचा

नई दिल्ली ,राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित एनसीआर में जहरीली हवा का कहर जारी है। शहर में स्मॉग की मोटी चादर छाई हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, बृहस्पतिवार सुबह सात बजे दिल्ली का औसत एक्यूआई (एयर क्वालिटी इंडेक्स) 'बेहद खराब' श्रेणी में 349 दर्ज किया गया है। इसके अलावा राजधानी के धौला कुआं इलाके में एक्यूआई 356, आनंद विहार में एक्यूआई 390, अलीपुर में 356, अशोक विहार में 388, चांदनी चौक में 371 और आईटीओ में 357 दर्ज किया गया है, जिसे 'बहुत खराब' कैटेगरी में रखा गया है। वहीं, बवाना में एक्यूआई 405, बुराड़ी एक्यूआई में 369, जहांगीरपुरी एक्यूआई में 394, नरेला एक्यूआई में 388 और द्वारका में एक्यूआई 348 दर्ज किया गया है।

फांसी के बाद जमीन घोटाले मामले में शेख हसीना को मिली 21 साल कैद की सजा, बेटे -बेटी को भी हुई जेल

ढाका एजेंसी । बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को 21 साल की जेल की सजा सुनाई गई। अदालत ने यह फैसला ढाका के पुर्बाचल प्लॉट घोटाले में दर्ज तीन मामलों में सुनाया है। साथ ही तीन में से एक मामले में शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद और बेटी साइमा वाजेद को पांच-पांच साल की जेल हुई। बांग्लादेशी मीडिया के अनुसार, इस मामले में बाकी 20 आरोपियों में से 19 को अलग-अलग सजा सुनाई गई। इसके अलावा, एक शख्स को तीनों मामलों में बरी कर दिया गया। ढाका की स्पेशल जज कोर्ट-5 के जज मोहम्मद अब्दुल्ला अल मामून ने कोर्ट रूम में शेख हसीना की गैरमौजूदगी में यह फैसला सुनाया है। बता दें कि इससे पहले बांग्लादेश क्राइम ट्रिब्यूनल ने उन्हें पांच में से तीन मामलों में दोषी करार दिया और एक मामले में मौत की सजा तो वहीं दूसरे मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है। आईसीटी ने पिछले साल जुलाई में हुए विद्रोह के दौरान मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए 17 नवंबर को यह निर्णय दिया था। एंटी-करप्शन बॉडी ने 12 से 14 जनवरी के बीच अपने ढाका इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस-1 में पुर्बाचल न्यू टाउन प्रोजेक्ट के तहत

प्लॉट के बंटवारे में कथित भ्रष्टाचार को लेकर छह अलग-अलग मामले दर्ज किए। एसीसी ने पूर्व पीएम पर आरोप लगाया कि शेख हसीना ने वरिष्ठ 'राजुक' अधिकारियों के साथ मिलकर पुर्बाचल न्यू टाउन प्रोजेक्ट के सेक्टर 27 के डिप्लोमैटिक जोन में अपने लिए, अपने बेटे सजीब वाजेद, बेटी साइमा वाजेद, बहन शेख रेहाना और उनके बेटे रादवान मुजीब सिद्दीक बॉबी, और बेटी अजमीना सिद्दीक के लिए गैर-कानूनी तरीके से छह प्लॉट हासिल किए। हर प्लॉट 10 कट्ठा का है।

विदेश | ऊर्जा और तेल के क्षेत्र में संभावना

डॉ. हिफ्जुर रहमान लीबिया में भारत के राजदूत नियुक्त,सहयोग बढ़ाना होगी प्राथमिकता

एजेंसी

नई दिल्ली, भारत ने लीबिया में डॉ. हिफ्जुर रहमान को अपना राजदूत नियुक्त किया है। हिफ्जुर रहमान वर्तमान में चाड रिपब्लिक के भारतीय राजदूत हैं। विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है कि वह जल्द ही अपनी जिम्मेदारी संभाल सकते हैं।

भारत के विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को डॉ. हिफ्जुर रहमान की नियुक्ति की है। उन्होंने मिडिल ईस्ट (सऊदी अरब, सीरिया और ट्यूनीशिया) में लंबे समय तक राजनयिक की जिम्मेदारी संभाली है। इस वजह से उन्हें अरब की राजनीति, संस्कृति और अर्थव्यवस्था की समझ है।

राजनयिक के साथ-साथ इनके पास प्रशासन, व्यापार, वाणिज्य और सांस्कृतिक अनुभव भी है, चूंकि वह चाड के भी राजदूत रह चुके हैं। ऐसे में उनके पास अफ्रीकी राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक-आर्थिक हालात, और भारत-अफ्रीका रिश्तों की गहराई से समझ है। हिफ्जुर रहमान इसका इस्तेमाल लीबिया और भारत के बीच संबंधों को मजबूत करने में लगा सकते हैं। लीबिया में भारत की कई प्राथमिकताएं हैं, उनमें सबसे अहम वहां रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा है। इसके अलावा ऊर्जा और तेल के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाना भी भारत की प्राथमिकता है। बता दें, लीबिया अफ्रीका का बड़ा तेल उत्पादक देश है। ऐसे में भारतीय राजदूत का अनुभव तेल आयात में स्थिरता लाने में काम आ सकता है। हालांकि, लीबिया में एक बड़ी चुनौती भी है। लीबिया की राजनीति में मिलिशिया और बाहरी हस्तक्षेप काफी ज्यादा होते हैं। ऐसे में भारत के लिए बड़ी चुनौती स्थिरता है। भारत के लिए ये अहम है कि इन हस्तक्षेपों के बावजूद भी वह अपनी रणनीतिक प्राथमिकताओं के अनुरूप काम करे। कई भारतीय कंपनियां लीबिया में काम कर रही हैं। भारत की कंपनियों ने लीबिया में बुनियादी ढांचा, पावर सेक्टर, तेल-गैस, निर्माण, ऊर्जा, हाउसिंग, अस्पताल, स्कूल, सड़कों, ट्रांसमिशन लाइन्स समेत अन्य क्षेत्रों में काम किए हैं। लीबिया में 2011–2019 के गृह संघर्ष और राजनीतिक अस्थिरता की वजह से दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध कुछ खास नहीं हैं। हालांकि, 2024–2025 में दूतावास की फि र से शुरुआत और नागरिकों की वापसी को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि दोनों देशों के व्यापारिक संबंध में फिर से सुधार देखने को मिलेगा। अगर ऐसा होता है तो न केवल दोनों देशों के बीच नए समझौते होंगे, बल्कि पुराने प्रोजेक्ट्स को फि र से शुरू किया जा सकेगा।

नेपाल ने 100 रुपये में भारत के 3 क्षेत्रों को दिखाया अपना हिस्सा

काठमांडू: एजेंसी

नेपाल ने भारत से फि र पंगा ले लिया है। नेपाल ने इस बार बिलकुल चीन जैसी हरकत की है। उसने अपने 100 रुपये की नई करेंसी पर भारत के 3 क्षेत्रों को अपना दिखाकर नया विवाद पैदा कर दिया है। इससे दोनों देशों के बीच फिर से संबंधों में बड़ा तनाव आने की आशंका है। बता दें कि नेपाल के केंद्रीय बैंक ने गुरुवार को 100 रुपये का नया नोट जारी किया, जिसमें देश का संशोधित राजनीतिक मानचित्र छपा है।

भारत के इन क्षेत्रों पर नेपाल ने किया अपना दावा - 100 रुपये की करेंसी में छपे इस मानचित्र में नेपाल ने विवादित कालापानी, लिपुलेख और लिंपियाधुरा क्षेत्रों को अपने देश के हिस्से के रूप में दिखाया है। भारत ने इस कदम को ÷एकतरफा÷ और ÷कृत्रिम क्षेत्रीय विस्तार÷ करार दिया है। नेपाल राष्ट्र बैंक (एनआरबी) द्वारा जारी इस नए नोट पर पूर्व गवर्नर डॉ. महाप्रसाद अधिकारी के हस्ताक्षर हैं तथा जारी करने की तिथि विक्रम संवत 2081 (2024 ईस्वी) अंकित है। तत्कालीन प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली के नेतृत्व वाली सरकार ने मई 2020 में संसद से संविधान संशोधन पारित कर कालापानी, लिपुलेख और लिंपियाधुरा को अपने क्षेत्र में शामिल करते हुए नए मानचित्र को आधिकारिक मान्यता दी थी। उसी संशोधित मानचित्र को अब 100 रुपये के नोट पर छापा गया है।

पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली की करतूत - इसे पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की करतूतों का नतीजा बताया जा रहा है, जिन्हें हाल ही में जेन-जी के आंदोलन में अपदस्थ कर दिया गया था। एनआरबी के प्रवक्ता गुणाकर भट्ट ने स्पष्ट किया कि नेपाल के बैंक नोटों में सिर्फ 100 रुपये के नोट पर ही देश का मानचित्र छपा होता है। 5, 10, 20, 50, 500 और 1,000 रुपये के नोटों पर कोई मानचित्र नहीं होता। उन्होंने कहा, ÷पुराने 100 रुपये के नोट में भी यही मानचित्र था; अब केवल उसे सरकार के नवीनतम निर्णय के अनुरूप अपडेट किया गया है।÷

भारत ने दर्ज कराई कड़ी आपत्ति

भारत ने नेपाल की इस हरकत पर बहुत ही कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। भारत ने दोहराया है कि लिपुलेख, कालापानी और लिंपियाधुरा उसके अभिन्न अंग हैं और नेपाल का यह कदम तथ्यात्मक रूप से गलत तथा स्वीकार्य नहीं है। नेपाल की सीमा पांच भारतीय राज्यों- सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड- से 1,850 किलोमीटर से अधिक लंबाई में लगती है। दोनों देशों के बीच इस क्षेत्र को लेकर लंबे समय से सीमा विवाद चल रहा है।

श्रीलंका में 'जल प्रलय' मूसलाधार बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से भारी तबाही, 31 की मौत, 14 लापता

नई दिल्ली एजेंसी

श्रीलंका में पिछले 11 दिनों से जारी मूसलाधार बारिश, बाढ़ और विनाशकारी भूस्खलन ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। श्रीलंका के आपदा प्रबंधन केंद्र ने गुरुवार को बताया कि इन आपदाओं के कारण अब तक 31 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि लगभग 4,000 लोग प्रभावित हुए हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार, अकेले मध्य पर्वतीय जिलों में 18 लोगों की मौत हुई है। डेली मिरर ऑनलाइन की खबर के अनुसार एक भयावह घटना में, कुंबुक्कना में बढ़ते जलस्तर के बीच एक यात्री बस फंस गई, जिसके बाद आपात दलों ने 23 यात्रियों को सफलतापूर्वक बचा लिया।

लोकशक्ति
www.lokshakti.in

शहर में प्रस्तावित फ्लाईओवर 1700 करोड़ से अधिक की लागत से तैयार होगा

बिलासपुर। राजीव गांधी चौक से लेकर सरकंडा महामाया चौक तक लंबा फ्लाईओवर जल्द आकार लेगा। सेतु निगम विभाग ने डिजाइन तैयार कर ली है। पत्थर तलाश व अन्य कार्यों के लिए सर्वे का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। फ्लाईओवर बनने से राजीव गांधी चौक पर आकर सरकंडा या रतनपुर क्षेत्र जाने वाले वाहन इस मार्ग के तीन सिग्नलों मंदिर चौक, नेहरू चौक व महामाया चौक को बाइपास करते हुए निर्बाध रूप से निकल जाएंगे। वहीं, नीचे पुरानी सड़क पर भी निर्माण से चौड़ाई पर ज्यादा असर नहीं होगा, जिससे बिना बाधा के यातायात चलती रहेंगी। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इसके लिए शासन को स्वीकृति के लिए भेजा गया है। शासन से अनुमति मिलने के बाद कार्य शुरू कर दिया जाएगा। अधिकरियों के अनुसार, फ्लाईओवर की शुरुआत राजीव गांधी चौक से होगी और यह राजेंद्र नगर चौक, मंदिर-चौक, नेहरू चौक होते हुए महामाया चौक तक पहुंचेगा। इसके बाद इसे दो दिशाओं में विस्तारित किया जाएगा। इससे मुख्य सड़क पर वाहनों का दबाव कम होगा। नया फ्लाईओवर बनने में लगभग 1,730 करोड़ रुपये की लागत आएगी। फ्लाई ओवर बन जाने से शहर

को ट्रैफिक जाम से बड़ी राहत मिलेगी, खासकर पिक आवर्स में। ज्ञात हो? बीते कुछ वर्षों में शहर की ट्रैफिक व्यवस्था पर लगातार लोड बढ़ता ही जा रहा है। खासतौर पर शाम के समय राजीव गांधी चौक से लेकर महामाया चौक तिराहे व पास के चौराहों पर लंबा जाम लग जाता है। फ्लाईओवर के निर्माण से न सिर्फ ट्रैफिक का दबाव कम होगा बल्कि सड़क हादसों की आशंका भी घटेगी।।प्रस्तावित फ्लाईओवर महामाया चौक के पासवर्ड सेप में दोनों ओर से आगे बढ़ेगा।

शहर के बीचों-बीच बनती है रोज जाम की स्थिति

राजीव गांधी चौक, मंदिर चौक, नेहरू चौक और महामाया चौक पर रोजाना सुबह और शाम जाम लगना आम बात है। वाहनों की लंबी कतारे, रंगती ट्रैफिक और बढ़ती परेशानी ने लोगों को हलकान कर रखा है। फ्लाईओवर बनने से रोजमर्रा की दिक्कत से शहरवासियों को बड़ी राहत मिलेगी।

शासन को स्वीकृति हेतु डीपीआर भेजा गया

स्वीकृति का इंतजार अधिकारियों का कहना है कि कार्ययोजना व डिजाइन तैयार हो चुकी है। शासन को डीपीआर भेजा गया है, शासन से जल्द मंजूरी मिल सकती है. डीपीआर आने के बाद योजना का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। राजीव गांधी चौक से महामाया चौक तक बनने वाले फ्लाईओवर के निर्माण पूर्ण होने के बाद लोगों को काफी राहत मिलेगी, क्योंकि जिसे राजीव गाधी चौक से सरकंडा जाना होगा वह सीधे चला जाएगा। इससे इंदिरा सेतु ब्रिज पर भी यातायात का दबाव कम होगा व जाम की स्थिति निर्मित नहीं होगी।

कृषि महाविद्यालय, रायपुर में संविधान दिवस मनाया गया कृषि महाविद्यालय

रायपुर। राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) इकाई, कृषि महाविद्यालय, रायपुर द्वारा 26 नवंबर को संविधान दिवस का आयोजन किया। कार्यक्रम महाविद्यालय के सेमिनार हॉल में आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र, छात्राए एवं प्राध्यापक गण उपस्थित थे।

कार्यक्रम का शुभारंभ भारत रत्न एवं संविधान निर्माता डॉ. बाबासाहब बी.आर. अंबेडकर के छायाचित्रपर पुष्पांजलि के साथ हुआ, इसके बाद मुख्य अतिथि अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, रायपुर डॉ. आरती गुहे द्वारा उपस्थित सभी छात्र छात्राओ एवं प्राध्यापको को संविधान की प्रस्तावना का वाचन कर शपथ दिलाई, जिसका सभी ने अनुकरण किया। इसके पश्चात, छात्रों द्वारा संविधान पर अपने विचार साझा किए और डॉ. गुहे ने उन्हें न्यायपूर्ण और समृद्ध समाज के निर्माण के लिए प्रेरित किया। डॉ. गुहे ने अपने संबोधन में कहा कि संविधान हमारे देश की मूलभूत संरचना है और हमें इसके मूल्यों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए।

कार्यक्रम में निबंध, पोस्टर, और रंगोली प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं, जिसमें महाविद्यालय के छात्र एवं छात्राओं ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को संविधान के प्रति जागरूक करना एवं संविधान के मूल्यों को अपने दैनिक जीवन में अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मप्रित करना है।

एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी (छात्र ईकाई) डॉ. संजय कुमार भारिया और एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी (छात्रा ईकाई) डॉ. पायल जायसवाल द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम मे विशिष्ट अतिथि डॉ. पी.के. सांगोडे कार्यक्रम समन्वयक, रा. से. यो. इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर उपस्थित थे। अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यक्रम का सफलतापूर्वक समापन हुआ।

गर्भावस्था से लेकर 1 साल तक किलकारी कार्यक्रम से किया जाता है माँ बच्चे का देखभाल

सारंगढ़ बिलाईगढ़ । शासन के निर्देशानुसार जिला में किलकारी एवं मोबाइल एकेडमी का कार्ययोजना निर्माण हेतु कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला डाटा प्रबंधक, राज्य सलाहकार एवं संभागीय सलाहकार किलकारी एवं मोबाइल एकेडमी, बीडीएम, काउंसलर, मितानिन कार्यक्रम के जिला एवं विकासखंड समन्यवक एवं कनिष्ठ सचिव सहायक एवं काउंसलर अन्य संबंधित अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित थे।

कार्यशाला में बताया गया कि गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के चौथे महीने से लेकर बच्चे के 1 साल होने तक प्रत्येक सप्ताह उनकी गर्भावस्था के महीने एवं नयी माताओं को बच्चे के उम्र के हिसाब से आईवीआर आधारित ऑडियो संदेश फोन कॉल के रूप मे भेजते है, जिसमें माता एवं बच्चों के सेहत, पोषण, परिवार नियोजन, टीकाकरण एवं अन्य सेवाओं के बारे में सही समय पर सटीक और प्रासंगिक जानकारी दिया जाता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना एवं पोषण संबंधित व्यवहारों में सुधार लाना है। जिले की उपलब्धि की जानकारी प्रस्तुत कर जिला कार्य योजना की रूपरेखा तैयार करने की भूमिका बताई गई एवं आरसीएच पोर्टल पर सही मोबाईल नम्बर प्रविष्टि हेतु निर्देशित किया। आरसीएच में पंजीयन होने के बाद गर्भावस्था के चौथे माह से किलकारी के 1600403660 नंबर से कॉल आना शुरू हो जाता है। इस नम्बर को डॉ अनीता के नाम से हितग्राही के मोबाईल में सेव करने के लिए निर्देशित किया गया है। यदि किसी कारणवश महिला किलकारी से आने वाले कॉल नहीं उठा पाती या उस सप्ताह के संदेश को फिर से सुनना चाहती है तो वह इसे सुनने के लिए 14423 डायल कर सकती है।

छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय सुवानृत्य एवं गीत–सुआ नृत्य एवं गीतों में छत्तीसगढ़ माटी की सोंधी खुशबू रची बसी

बिलासपुर । छत्तीसगढ़ की परंपरा में सुवा नृत्य का विशेष महत्व है। सुआ का मतलब तोता होता है। इस नृत्य को लेकर अलग-अलग मान्यताएं हैं। यह नृत्य खासकर छत्तीसगढ़ के अंचलों में किया जाता है। इस विधा में नृत्य के साथ-साथ सुमधुर सुवा गीत भी महिलाओं द्वारा सामूहिक रूप से गाए जाते हैं । इस नृत्य में महिलाएं और लड़कियां एक बांस की टोकरी में चावल रखकर उसमें मिट्टी से बना तोता रखती हैं। इस बांस की टोकरी को लेकर लड़कियां और महिलाएं समूह में घूमती हैं और सुआ नृत्य करती हैं। नृत्य के साथ-साथ महिलाएं गीत भी गाती हैं और ताली बजाती हैं।सुआ नृत्य गीत कुमारी कन्याओं तथा विवाहित स्त्रियों द्वारा समूह में गाया और नाचा जाता है। इस नृत्य गीत के परंपरा के अनुसार बाँस की बनी टोकरी में धान रखकर उस पर मिट्टी का बना, सजाया हुआ सुवा रखा जाता है। लोक मान्यता है कि टोकरी में विराजित यह सुवा की जोड़ी शंकर और पार्वती के प्रतीक होते हैं।

मान्यताओं के अनुसार जब महिलाएं गांव में किसानों के घर सुवा गीत नृत्य करने जाती थीं, तो उन्हें उस नृत्य के लिए उपहार स्वरूप पैसे या अनाज दिए जाते थे। इसका उपयोग गौरा-गौरी के विवाह उत्सव में किया जाता है। इस नृत्य की दूसरी मान्यता यह है कि सुआ नृत्य की शुरुआत दिवाली के दिन से की जाती है। जिसका मतलब है कि धान की फसल कट चुकी है। अब खुशियों के दिन आ गए हैं।सुआ गीत की मान्यता यह है कि सुआ गीत नृत्य करने महिलाएं जब गांव में किसानों के घर-घर जाती थीं. तब उन्हें उस नृत्य के उपहार स्वरूप पैसे या अनाज दिया जाता है. इसका उपयोग गौरा-गौरी के विवाह उत्सव में करती हैं।

इस नृत्य की दूसरी मान्यता यह है कि सुआ नृत्य की शुरुआत दीपावली के दिन से की जाती है, और ऐसा माना जाता है कि दीपावली तक किसानों के खेतों में से धान की फसल कट जाया करते थे. इसी की खुशी में घर-घर जाकर युवतियाँ यह नृत्य किया करती थी और उपहार स्वरूप उन्हें नया अनाज दिया जाता था। यह नृत्य, छत्तीसगढ़ की आदिवासी संस्कृति का अहम हिस्सा है। यह नृत्य, भगवान की पूजा से जुड़ा है। सुआ नृत्य में, महिलाएं बांस के बर्तन में तोता रखती हैं और उसके चारों ओर घूमकर नृत्य करती हैं। सुआ नृत्य, दीपावली के दिन से शुरू होकर अगहन महीने तक चलता है। सुआ नृत्य में, महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में सजती हैं और अपने सिर पर घुंघरू बांधती हैं।सुआ नृत्य के ज़रिए, महिलाएं अपने जीवन के अलग-अलग पहलुओं और पारिवारिक भावनाओं को व्यक्त करती हैं।

सुआ नृत्य के दौरान गाए जाने वाले गीतों में, जीवन की कठिनाइयों, प्रेम, विरह, और धार्मिक मान्यताओं का वर्णन होता है। सुआ नृत्य में, महिलाएं तोते के ज़रिए संदेश देती हैं। सुआ नृत्य करने वाली महिलाओं को, लोग उपहार स्वरूप चावल, धान, या पैसे देते हैं।सुआ नृत्य की शुरुआत दीपावली के दिन से की जाती है। सुवा नृत्य गीत कुमारी कन्याओं तथा विवाहित स्त्रियों द्वारा समूह में गाया और नाचा जाता है। इस नृत्य गीत के परंपरा के अनुसार बाँस की बनी टोकरी में धान रखकर उस पर मिट्टी का बना, सजाया हुआ सुवा रखा जाता है।

सुआ गीत छत्तीसगढ़ राज्य के गोंड स्त्रियों का नृत्य गीत है। यह दीपावली के पर्व पर महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला गीत है। इस लोकगीत में स्त्रियां तोते के माध्यम से संदेश देते हुए गीत गाती हैं। इस गीत के जरिए स्त्रियां अपने मन की बात बताती हैं, इस विश्वास के साथ कि वह (सुवा) व्यथा उनके प्रिय तक पहुँचेगी।सुआ नृत्य के महत्व का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि गांव हो या शहर हर तरफदीपावली के अवसर पर छोटी बच्चियों से लेकर बड़ी बुजुर्ग महिलाओं तक सुआ नृत्य करते दिखाई दे जाती हैं।

निर्माण कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, जिला पंचायत सीईओ गोकुल रावटे, मनरेगा व आवास योजनाओं की सतत मॉनिटरिंग

जांजगीर-चांपा। जिला पंचायत सीईओ गोकुल रावटे ने शुक्रवार को जिला पंचायत सभाकक्ष में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक लेकर स्पष्ट कहा कि निर्माण कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी और सभी परियोजनाओं को निर्धारित गुणवत्ता व समय-सीमा के भीतर पूरा किया जाए। उन्होंने मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, 15वें वित्त आयोग, जिला व जनपद पंचायत विकास निधि, मुख्यमंत्री आंतरिक विद्युतीकरण योजना तथा डीपीआरसी प्रशिक्षण समेत प्रमुख योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की।

सीईओ ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी कार्यों में पारदर्शिता, गुणवत्तापूर्ण निर्माण और जन-सहभागिता सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा कि स्वीकृत कार्यों के क्रियान्वयन में तेजी लाते हुए मैदानी अमला गांवों में नियमित भ्रमण कर

स्थलों का निरीक्षण करे। बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) वर्ष 2025-26 के अंतर्गत स्वीकृत नए आवासों की राशि हितग्राहियों के खातों में अंतरित कर दी गई है। सीईओ ने निर्देश दिए कि आवास निर्माण कार्यों में किसी भी प्रकार की देरी न हो और जिन आवासों का निर्माण प्रारंभ नहीं हुआ है, उन्हें तत्काल शुरू कराया जाए। इसके लिए मस्टर रोल जारी करने, मैदानी स्तर पर सक्रियता बढ़ाने और विभागीय समन्वय को मजबूत करने पर जोर दिया गया।

मनरेगा के तहत अनुमोदित कार्यों, मजदूरी भुगतान, सामाजिक अंकेक्षण और परिसंपत्तियों के संरक्षण की भी समीक्षा की गई। सीईओ ने लंबित मस्टर रोल, मजदूरी और सामग्री भुगतान में देरी नहीं होने देने के निर्देश दिए। उन्होंने लंबित सामाजिक अंकेक्षण मामलों के त्वरित निराकरण, जल संरक्षण, नाला मरम्मत, खेत-तालाब, वृक्षारोपण और एनआरएम कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मनरेगा के माध्यम से ग्रामीणों को अधिक रोजगार उपलब्ध कराएं और निर्मित परिसंपत्तियों का सतत उपयोग सुनिश्चित किया जाए। साथ ही ग्राम पंचायत भवनों में क्यूआर कोड लगाने, युक्तधारा पोर्टल में लक्ष्य अनुसार कार्य स्वीकृति, एनआरएम एवं कृषि श्रेणी के कार्यों में निर्धारित व्यय सुनिश्चित करने और ईएमबी के माध्यम से समयबद्ध मूल्यांकन-सत्यापन तथा एरिया ऑफिसर ऐप में आवास व मनरेगा कार्यों का नियमित निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए।

बैठक में अमृत सरोवरों को ग्रामीण आजीविका संवर्धन का साधन बनाने पर विशेष बल दिया गया। सीईओ ने कहा कि ग्रामीणों को मत्स्य पालन हेतु प्रेरित कर सरोवरों में मत्स्य बीज डालने की प्रक्रिया मत्स्य विभाग के सहयोग से सुनिश्चित की जाए। उन्होंने हितग्राहियों को रेन वाटर हार्वेस्टिंग और सोखता गड्ढा निर्माण के लिए प्रोत्साहित करने तथा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लाभों का अधिकाधिक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए। जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के लक्ष्यों की पूर्ति और लाभार्थियों को सशक्त बनाने के लिए सतत निगरानी और तेज क्रियान्वयन जारी है।

कांडराजा में प्रस्तावित बॉक्साइट खदान के विरोध में ग्रामीण आंदोलित

खदान खुलने से जलस्तर में गिरावट, वायु प्रदूषण में वृद्धि और हाथियों के प्राकृतिक गलियारे के बाधित होने की आशंका है।

बिलासपुर। मैनपाट, में 27 नवम्बर 2025 कांडराजा (मैनपाट) के हाथी प्रभावित और पर्यावरणीय रूप से अति-संवेदनशील क्षेत्र में प्रस्तावित बॉक्साइट खदान को लेकर ग्रामीणों में गहरा आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन ने बिना ग्रामसभा की वास्तविक सहमति के खनन की अनुमति देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिससे पारदर्शिता और जनभागीदारी पर गंभीर प्रश्न उठ रहे हैं। स्थानीय निवासियों के अनुसार 137 हेक्टेयर क्षेत्रफल में प्रस्तावित इस परियोजना की जनसुनवाई आगामी 30 नवम्बर 2025 को तय की गई है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि जिस भूमि को शासन द्वारा ÷बंजर÷ बताया जा रहा है, वहां वर्षों से खेती होती रही है और वर्तमान में भी तुअर (अरहर) जैसी फसलें खड़ी हैं। कई किसानों के भूमि पट्टे बिना पर्याप्त कारण बताए निरस्त कर दिए गए हैं, जिससे आजीविका पर संकट मंडरा रहा है।ग्रामीणों का कहना है कि खदान खुलने से जलस्तर में गिरावट, वायु प्रदूषण में वृद्धि और हाथियों के प्राकृतिक गलियारे के बाधित होने की आशंका है। साथ ही मैनपाट की प्रसिद्ध प्राकृतिक सुंदरता व पर्यावरणीय संतुलन को भी गहरा नुकसान पहुंचेगा।ग्रामीण समुदाय और सामाजिक संगठन 30 नवम्बर को जनसुनवाई में भारी संख्या में शामिल होकर शांतिपूर्ण विरोध दर्ज कराएंगे। उनका आरोप है कि कुछ स्थानों पर प्रशासनिक दबाव के माध्यम से तथाकथित सहमति प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि जनभावना इस परियोजना के स्पष्ट विरोध में है।ग्रामीणों ने शासन-प्रशासन से मांग की है कि कांडराजा क्षेत्र में पर्यावरण और स्थानीय आजीविका की रक्षा के लिए खदान की अनुमति रद्द की जाए। यदि खदान परियोजना आगे बढ़ाई गई, तो इससे मैनपाट के पारिस्थितिक संतुलन और ग्रामीणों के जीवन पर दीर्घकालिक दुष्प्रभाव पड़ेगा।

छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने प्रकरणों की जनसुनवाई

जांजगीर-चांपा। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने कलेक्ट्रोरेट सभाकक्ष जांजगीर में महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रस्तुत प्रकरणों पर जनसुनवाई की। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक की अध्यक्षता में आज प्रदेश स्तर की 352 व जांजगीर-चांपा जिले में 13 वीं सुनवाई हुई। इस दौरान विधायक अकलतरा राघवेन्द्र कुमार सिंह उपस्थित थे।

आज के सुनवाई के दौरान उभयपक्ष उपस्थित हुए। आवेदिका ने बताया कि 17 माह का वेतन प्रतिमाह 10,500 रूपए के अनुसार कुल 1,78,500 रूपए अब तक नहीं मिला है। अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से स्पष्ट है कि उच्च अधिकारियों को वेतन बकाया संबंधी पत्राचार किया गया है। उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 07.02.2025, 13.02.2025 एवं 20.02.2025 अनुसार 45 दिनों में भुगतान होना था, किंतु लगभग 7 माह बीत जाने के बाद भी भुगतान नहीं हुआ। अनावेदकगण ने कहा कि शासन से राशि प्राप्त होने पर ही भुगतान किया जाएगा। वेतन भुगतान न होने पर आवेदिका को समझाइश दी गई कि वह उच्च न्यायालय में अनावेदकगण एवं संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध अवमानना याचिका प्रस्तुत कर सकती हैं। आज की कार्यवाही की प्रति निःशुल्क प्रदान की गई तथा प्रकरण की अगली सुनवाई दो माह बाद रायपुर में रखी गई।

अन्य प्रकरण में आवेदका उपस्थित आवेदक लगातार अनुपस्थित है इस प्रकरण में पूर्व में ही आवेदिका को निर्देशित किया जा चुका है कि अनावेदक के खिलाफएफआईआर दर्ज कराए जिस पर आवेदिका ने अब तक आवेदिका ने अब तक एफआईआर दर्ज नहीं करा पायी है। आवेदिका को समझाईश दिया गया व न्यायालय में अनावेदक के खिलाफ परिवाद पत्र दाखिल करे और न्याय प्राप्त करे आवेदिका को आज की आर्डरशीट निःशुल्क दिया गया। और प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।

अन्य प्रकरण में आवेदिका एवं अनावेदक उपस्थित अनावेदन ने दस्तावेज प्रस्तुत किया जिसके अनुसार थाना अकलतरा जिला जांजगीर ने पुलिस थाना में आवेदिका की शिकायत पर अनावेदक एवं पत्नि के खिलाफ दिनांक 31.07.2023 को भादंस की धारा 420,465,467,471 एवं 34 के तहत् एफआईआर पंजीबद्ध किया जा चुका है। लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि इस प्रकरण में जांच कार्यवाही पूर्ण कर न्यायालय में प्रस्तुत हुआ है अथवा नहीं थाना अकलतरा से जानकारी लेकर पुनः प्रस्तुत करें। उपस्थित पुलिस कर्मचारी के माध्यम से उक्त उक्त एफआईआर पर चालान तैयार हुआ है लेकिन न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः इस मामले में केन्द्र प्रशासिका को निर्देशित किया है कि थाना अकलतरा से चालान प्रस्तुति की कापी प्राप्त कर आयोग में प्रस्तुत करें। उसे आज की आर्डरशीट की प्रति निःशुल्क प्रति दिया जाता है और सखी प्रशासिका को निःशुल्क प्रति दिया जाता है।

अन्य प्रकरण में आवेदिका उपस्थित हुई, अनावेदक अनुपस्थित रहा। आवेदिका ने बताया कि अनावेदक आरक्षक दंतेवाड़ा में पदस्थ है तथा परिवार न्यायालय जांजगीर के आदेश का पालन नहीं कर रहा है, जिसके तहत 7 लाख रूपए की राशि आवेदिका को देय है। आज की आदेशशीट के अनुसार आवेदिका 7 लाख रूपए मय ब्याज प्राप्त करने की अधिकारी है। आदेशशीट की प्रति निःशुल्क आवेदिका को प्रदान की गई।अन्य प्रकरण में अनावेदिका का पूरा पता देने में आवेदिका स्वयं को असमर्थ बताती है और उसकी बेटा की गुमशुदगी की भी रिपोर्ट लिखा चुकी है ऐसी दशा में आवेदिका का पूरा पता के अभाव में सुने जाने का काई औचित्य नहीं है आवेदिका सखी के माध्यम से अनावेदिका का पूरा पता प्राप्त कर दो माह में सूचित करें ताकि प्रकरण सुना जाना है या नहीं इस पर निर्णय लिया जा सके।

अन्य प्रकरण में आवेदिका उपस्थित आनावेदक अनुपस्थित इस मामले में जमीन की फर्नी रजिस्ट्री किया गया है। आवेदिका की ओर से पुलिस थाना डभरा को लिखित शिकायत किया गया है।

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु नवीनीकरण और नवीन आवेदन 30 नवंबर तक आमंत्रित

शिक्षा सत्र 2025-26 के एसटी, एससी और ओबीसी वर्ग के युवाओं के लिए अवसर

सारंगढ़ बिलाईगढ़। आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अध्ययनरत विद्यार्थियों को सूचित किया गया है कि, वे शिक्षा सत्र 2025-26 के पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति छात्रवृत्ति के लिए विभागीय पोर्टल पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप डॉट सीजी डॉट एनआईसी डॉट इन में नवीनीकरण और नवीन आवेदन 30 नवंबर 2025 तक जमा कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के बाद शिक्षा सत्र 2025-26 के पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति छात्रवृत्ति के लिए विभागीय पोर्टल को बंद किया जाएगा। इसका संभावित भुगतान तिथि 31 दिसंबर निर्धारित है। विद्यार्थियों को आधार सीडेड बैंक खाते में भुगतान 7 कार्य दिवस में प्राप्त होगा।

छात्रवृत्ति हेतु पात्रता

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों के पालक की आय सीमा रू. 2.50 लाख और अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आय सीमा 1 लाख रूपये प्रतिवर्ष होना चाहिए। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण पत्र, छ.ग. का मूल निवास प्रमाण पत्र, विद्यार्थी के अध्ययनरत् पाठ्यक्रम के विगत वर्ष का परीक्षा परिणाम संलग्न करना होगा।

पीएफएमएस के माध्यम से आधार आधारित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा रहा है। अतः सभी विद्यार्थी ऑनलाईन आवेदन करते समय ध्यान रखे कि उनका बचत खाता एक्टिव हो एवं आधार सीडेड बैंक खाता नम्बर की प्रविष्टि करना सुनिश्चित करें। इस संबंध में विस्तृत जानकारी अपने जिले के कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास से प्राप्त की जा सकती है।

मोदी और अमित शाह के दौरे को लेकर रायपुर में कड़ी तैयारी

रायपुर । नवा रायपुर स्थित भारतीय प्रबंध संस्था (IIM) में 28 से 30 नवम्बर 2025 तक होने वाली DG Conference 2025 के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का तीन दिवसीय रायपुर प्रवास प्रस्तावित है। उनके आगमन को ध्यान में रखते हुए राजधानी में सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। संपूर्ण मार्ग व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाल रहे डीआईजी बस्तर रेंज प्रशांत अग्रवाल ने रायपुर जिले सहित अन्य इकाइयों से यातायात ड्यूटी पर लगाए गए अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने सभी कर्मचारियों को VVIP ड्यूटी के दौरान पूर्ण मुस्तैदी से कार्य करने, उत्तम टर्न आउट में तैनात रहने, VVIP मार्गों पर आवारा मवेशियों की रोकथाम सुनिश्चित करने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तत्काल सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को देने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन का कहना है कि पूरे कार्यक्रम के दौरान राज्य में सुरक्षा और यातायात व्यवस्था सर्वोच्च प्राथमिकता पर रहेगी।

इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में लिफ्ट हादसा, बड़ा हादसा टला

रायपुर । राजधानी रायपुर के इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में सोमवार रात एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। कॉलोनी के फेस–2 के त ब्लॉक में रात करीब 10 बजे लिफ्ट अचानक बेकाबू हो गई। सौभाग्य से इस दौरान कोई घायल नहीं हुआ।

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए लिफ्ट का बटन दबा रही थीं। जैसे ही लिफ्ट उनके फर्श पर पहुंचा और उन्होंने दरवाजा खोलने का प्रयास किया, लिफ्ट का वजन मशीन टूटकर ग्राउंड फ्लोर पर गिर गया और लिफ्ट तेजी से ऊपर की ओर चली गई, जिससे तेज धमाके की आवाज़ सुनाई दी। वीडियो में यह भी साफ नजर आया कि लिफ्ट में उस समय कोई सवारी नहीं थी, वरना गंभीर दुर्घटना हो सकती थी।

इस घटना के बाद कॉलोनी के निवासियों ने आरडीए पर आरोप लगाया कि सोसाइटी में लिफ्ट का नियमित और सही मेंटेनेंस नहीं किया जा रहा है। उनका कहना है कि करीब 15 दिन पहले भी लिफ्ट खराब हुई थी। उन्होंने बताया कि बार-बार शिकायत करने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई और लिफ्ट को केवल कामचलाऊ स्थिति में रखा गया है।निवासी इस बात से बेहद नाराज हैं और अब उचित मेंटेनेंस और सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग कर रहे हैं।

भाजपा कार्यालय में मनाया गया संविधान दिवस

रायपुर । भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय (कुशाभाऊ ठाकरे परिसर) में बुधवार को संविधान दिवस पर क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जम्वाल ने संविधान को नमन किया तथा संविधान निर्माताओं को स्मरण करते हुए उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर श्री जम्वाल ने कहा कि संविधान लोकतंत्र की गीता है। यह देश के मान, सम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक है। हम सबका कर्तव्य है कि हम इसे आत्मसात कर संविधान निर्माताओं के स्वप्नों को साकार करने प्रतिपल संकल्पित रहें। देश के सभी लोगों को संविधान का पालन करना चाहिए। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने मां भारती, डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी और पं. दीनदयाल उपाध्याय के तैल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की।

इस अवसर पर भाजपा प्रदेश महामंत्री अखिलेश सोनी, प्रदेश मंत्री विद्या सिदार, प्रदेश कार्यालय मंत्री अशोक बजाज, सह कार्यालय मंत्री प्रीतेश गांधी, मोहन पवार, अनुराग अग्रवाल, शंकर अग्रवाल एवं राकेश पांडे आदि उपस्थित थे।

नई श्रम संहिताओं से श्रमिकों को व्यापक सुरक्षा व अधिकार–ईएसआईसी

रायपुर । केंद्र सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा देशव्यापी रूप से लागू की जा रही चार नई श्रम संहिताओं–वेतन संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता तथा व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य-शर्त संहिता–का कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ ने स्वागत किया है। ईएसआईसी ने कहा कि ये संहिताएँ प्रदेश के श्रमिकों को बेहतर वेतन, सुरक्षित कार्यस्थल और व्यापक सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में एक नई निर्णायक शुरुआत हैं।

ईएसआईसी के लागू होने से छत्तीसगढ़ में ईएसआईसी कवरेज और लाभों में व्यापक विस्तार होगा। प्रावधानों के अनुसार अब पूरे देश में ऐसे प्रतिष्ठान जिनमें 10 से कम कर्मचारी कार्यरत हैं, वे स्वैच्छिक आधार पर पंजीकरण करा सकेंगे। वहीं खतरनाक गतिविधियों में संलग्न किसी भी प्रतिष्ठान को–चाहे केवल एक कर्मचारी ही क्यों न हो–अनिवार्य रूप से ईएसआईसी में पंजीकृत होना पड़ेगा।

उन्होंने यह भी बताया कि नई व्यवस्था के अंतर्गत 40 वर्ष से अधिक आयु के सभी कर्मचारियों के लिए नियोक्ताओं द्वारा वार्षिक निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण उपलब्ध कराना अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही संहिताएँ महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्यस्थल, समान अवसर एवं संवेदनशील व्यवस्था सुनिश्चित करती हैं। श्री कुमार ने कहा कि अब गिग एवं प्लेटफॉर्म आधारित श्रमिक भी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में शामिल किए जा रहे हैं, जिससे एक बड़े अनौपचारिक कार्यबल को औपचारिक सुरक्षा ढांचा प्राप्त होगा। ईएसआईसी के अनुसार इन संहिताओं के क्रियान्वयन से सामाजिक सुरक्षा, पारदर्शिता और औपचारिक रोजगार को प्रोत्साहन मिलेगा। समान वेतन, सुरक्षित कार्य परिस्थितियाँ और स्वास्थ्य लाभों के विस्तार से श्रमिकों के जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार होने की अपेक्षा है।

संग्रहण एवं डिजिटाइजेशन का शत–प्रतिशत काम पूर्ण करने वाले हर विधानसभा क्षेत्र के प्रथम तीन बीएलओ को किया

राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर दिए जाएंगे पुरस्कार, प्रशस्ति पत्र के साथ दी जाएगी पांच हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि

रायपुर । भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य में अर्हता तिथि 1 जनवरी 2026 के आधार पर मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर-2026) पूरे प्रदेश में व्यवस्थित एवं प्रभावी रूप से संचालित किया जा रहा है। इस पुनरीक्षण अभियान के सुचारू क्रियान्वयन में बीएलओ की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए उत्कृष्ट एवं समयबद्ध कार्य करने वाले बीएलओ को प्रशस्ति पत्र के साथ पुरस्कार राशि भी प्रदान की जाएगी।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अधिकारियों ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्धारित मानकों के अनुसार राज्य के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में जहाँ किसी भी भाग संख्या पर 800 या उससे अधिक पंजीकृत मतदाता हैं, वहाँ 28 नवम्बर 2025 तक गणना फॉर्म वितरण, संग्रहण एवं डिजिटाइजेशन का शत-प्रतिशत कार्य पूर्ण करने वाले प्रथम तीन बीएलओ को पुरस्कृत किया जाएगा। इसके अंतर्गत राज्य के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों से तीन-तीन बीएलओ यानि कुल 270 बीएलओ को 25 जनवरी 2026 को आगामी राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर आयोजित होने वाले जिला स्तरीय कार्यक्रमों में पुरस्कार दिए जाएंगे। पुरस्कार के लिए चयनित बीएलओ को प्रशस्ति पत्र के साथ पांच हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।

बीएलओ के चयन एवं अनुशंसा की प्रक्रिया संबंधित विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। ईआरओ द्वारा अनुशंसित बीएलओ ही पुरस्कार के लिए पात्र माने जाएंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री यशवंत कुमार ने सभी कलेक्टरों एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे पुरस्कार के लिए पात्र बीएलओ की पहचान, चयन एवं पुरस्कार वितरण से संबंधित सभी कार्यों को समयबद्ध रूप से सुनिश्चित करते हुए राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर बीएलओ को पुरस्कृत करने की तैयारियाँ पूर्ण करें।

महापौर ने विभिन्न वार्डों में जाकर मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण के कार्यों का लिया जायजा

सभी नागरिकों से जागरूक मतदाता के रूप में गणना पत्रक भरकर बीएलओ को देकर मजबूत लोकतंत्र कायम करने सहभागिता दर्ज करवाने की विनम्र अपील

रायपुर । रायपुर नगर पालिक निगम की महापौर श्रीमती मीनल चौबे ने निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार प्रगतिरत एसआईआर मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की प्रगति का प्रत्यक्ष निरीक्षण भाठागांव, रायपुरा, चंगोराभाठा, भारत माता चौक, गुढ़ियारी आदि विभिन्न स्थानों में किया। महापौर श्रीमती मीनल चौबे ने जोन कमिश्नरों, अधिकारियों, बीएलओ से एसआईआर कार्य की प्रगति की जानकारी ली और ड्यूटी पर लगाए गए जोन कार्यालय में मतदाताओं से प्राप्त गणना पत्रकों की कंप्यूटर पर डाटा एंट्री करवा रहे बीएलओ से चर्चा की और एसआईआर कार्य नियत समयावधि के भीतर गुणवत्तापूर्ण तरीके से त्रुटिरहित तरीके से पूर्ण करवाने कहा.इस दौरान नगर निगम जोन 5 अध्यक्ष श्री अंबर अग्रवाल की उपस्थिति रही। महापौर श्रीमती मीनल चौबे ने सभी नागरिकों से जागरूक मतदाता का परिचय देते हुए गणना पत्रक को तत्काल भरकर बीएलओ को देकर लोकतंत्र मजबूत बनाने में सहभागिता दर्ज करवाने की विनम्र अपील की।

55 लाख रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी अरूण साव ने

रायपुर । उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने लोरमी विकासखंड के शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डिंडौरी में क्षेत्र के विकास और शैक्षणिक वातावरण को सुदृढ़ बनाने के लिए महत्वपूर्ण घोषणा की। विद्यालय की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए परिसर में बाउंड्रीवाल निर्माण के लिए 25 लाख रुपए स्वीकृत करने की घोषणा की, जिससे विद्यार्थियों को सुरक्षित और सुव्यवस्थित शैक्षणिक वातावरण मिल सकेगा। इसके साथ ही गांव में सामुदायिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने एवं गांव में सामाजिक समरसता को मजबूत करने के उद्देश्य से 20 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक भवन निर्माण की घोषणा की। वहीं, ग्रामीण परिवहन व आवागमन को सुविधाजनक बनाने के लिए 10 लाख रुपए की लागत से सीसी रोड बनाने की घोषणा की।

संविधान दिवस महानदी मंत्राल में अधिकारियों–कर्मचारियों को मुख्य सचिव ने दिलाई शपथ

रायपुर । संविधान दिवस पर आज राजधानी के महानदी मंत्रालय, विधानसभा सचिवालय, राजभवन सहित भाजपा, कांग्रेस कार्यालयों में संविधान को सफल बनाने की शपथ ली गई तथा पुष्पांजलि अर्पित की गई।मिली जानकारी के अनुसार राज्यपाल रमेन डेका की अनुपस्थिति में सचिव सीआर प्रसन्ना ने कर्मचारियों को संविधान का निष्ठापूर्वक पालन करने की शपथ दिलाई है। प्रधानमंत्री की आगमन को देखते हुए यहां पर राज्यपाल रमेन डेका कल आने वाले हैं। विधानसभा सचिवालय में सचिव दिनेश शर्मा की उपस्थिति अलग-कक्षों में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गईं है। राज्य में विधानसभा सत्र को देखते हुए पुरानी विधानसभा में ही पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई है। कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने भी बताया कि संविधान के प्रति निष्ठा रखने की शपथ कार्यकर्ताओं ने ली है।

मंत्री राजेश अग्रवाल 50.31 लाख रुपए की लागत से ग्राम पंचायत खैरबार में गौरवपथ निर्माण का भूमिपूजन

लागत से ग्राम पंचायत खैरबार में गौरवपथ निर्माण का किया भूमिपूजन

रायपुर।

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल के प्रयासों से सरगुजा जिले में लगातार विकास कार्य हो रहे हैं। इसी कड़ी में अम्बिकापुर विकासखण्ड के ग्राम पंचायत खैरबार में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना के तहत 50.31 लाख रुपए की लागत से 500 मीटर लंबे गौरवपथ सह नाली निर्माण का भूमि पूजन किया गया। इस महत्वपूर्ण भूमि पूजन समारोह में मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने निर्माण कार्य की शुरुआत करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों के स्वरूप को बेहतर बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की।

श्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाजनक आवागमन, आर्थिक समृद्धि और समग्र विकास सुनिश्चित करने वाली एक प्रमुख योजना है। गौरवपथ और नाली निर्माण से ग्रामीण इलाकों की सड़कें मजबूत होंगी, जिससे वर्षा के मौसम में आवागमन सुगम होगा। मंत्री ने कहा कि ये प्रयास मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में निरंतर जारी हैं और उनके मार्गदर्शन में सरगुजा में कई सड़क निर्माण और विकास कार्य हो रहे हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और पर्यटन मंत्री श्री राजेश अग्रवाल को इस क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों के लिए धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सरगुजा जिले में अब तक कई किलोमीटर सड़कों का निर्माण हो चुका है, जिनमें ग्राम गौरवपथ योजना के तहत सीमेंट कांक्रीट सड़कों का निर्माण प्रमुख है। सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए समर्पित है और मंत्री श्री राजेश अग्रवाल के नेतृत्व में यह क्षेत्र तेजी से विकास की ओर अग्रसर है। भूमिपूजन के अवसर पर अध्यक्ष जिला पंचायत सरगुजा श्रीमती निरूपा सिंह, सदस्य जिला पंचायत श्रीमती दिव्या सिंह सिसोदिया, सदस्य जनपद पंचायत अम्बिकापुर श्रीमती अनामिका पैकरा, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के कर्मचारी एवं स्थानीय ग्रामीण मौजूद थे।

एसआईआर, छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट धमतरी और बस्तर की करेंगे समीक्षा

रायपुर । राजधानी में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के काम तेजी आ गई है। यद्यपि यह कार्य काफी कठिन है, लेकिन भूल-भुलैया के बीच मतदाताओं के मतदान केन्द्र और 2003 की सूची को खोजने को लेकर पेज लग गया है। इधर छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट भी राजधानी रायपुर पहुंच गए हैं। यहां से वे सीधे धमतरी रवाना हो गए हैं।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज से मिली जानकारी के राज्य में एसआईआर को लेकर सचिन पायलट एक महत्वपूर्ण बैठक एवं समीक्षा बैठक लेंगे। ज्ञात रहे कांग्रेस एसआईआर का विरोध कर रही है। आज सचिन पायलट रायपुर पहुंचे। यहां वे सीधे कुरूद रवाना हुए यहां पर वे संविधान सभा की महत्वपूर्ण बैठक लेंगे। कांग्रेस ने बूत लेवल पर बीएलए नियुक्त किया है, जो कि घर-घर जाकर मतदाताओं से संपर्क कर रहा है। प्रदेश सहित गांवों में भी यह काम तेजी से चल रहा है। गांवों की अपेक्षा शहर में मतदाता सूची में नाम खोजने में बहुत कठिन काम हो गया है। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार सचिन पायलट छत्तीसगढ़ के प्रभारी बस्तर और कुरूद में जाकर एसआईआर की समीक्षा करेंगे। छत्तीसगढ़ में अर्हता तिथि 01 जनवरी 2026 के लिए मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य का संचालन 04 नवम्बर 2025 से पूरी गंभीरता और पारदर्शिता के साथ जारी है। बीएलओ द्वारा प्रदेशभर में घर-घर जाकर पंजीकृत मतदाताओं के गणना प्रपत्रों का संग्रहण एवं डिजिटाइजेशन तेजी से प्रगति पर है।

जमीन गाइडलाइन दरों में भारी बढ़ोतरी के खिलाफ सत्यमेव जयते फाउंडेशन करेगा

कन्हैया अग्रवाल ने कहा बढ़ी गाइडलाइन आम आदमी के घर के सपने पर गहरी चोट

रायपुर । संवाददाता। छत्तीसगढ़ में भूमि गाइडलाइन दरों में की गई भारी-भरकम बढ़ोतरी के खिलाफ सत्यमेव जयते फाउंडेशन ने प्रदेशव्यापी बड़े आंदोलन की घोषणा की है । फाउंडेशन के प्रदेश संयोजक कन्हैया अग्रवाल ने कहा कि यह बढ़ोतरी बेहद अव्यवहारिक, जनविरोधी और आम जनता की क्षमता के विपरीत है, जिससे लाखों परिवारों का घर बनाने का सपना चकनाचूर हो जाएगा । श्री अग्रवाल ने कहा कि गाइडलाइन दरें सिर्फ कागजों पर अंकित दस्तावेज नहीं बल्कि उन्हीं के आधार पर रजिस्ट्री शुल्क, स्टांप शुल्क, परिसंपत्ति की कीमत और आवास निर्माण की लागत तय होती है । इतने बड़े पैमाने पर की गई अप्रत्याशित बढ़ोतरी का सीधा असर हर उस परिवार पर पड़ेगा जो अपना छोटा सा घर बनाने के लिए जमीन खरीदना चाहता है । उन्होंने कहा कि यह फैसला मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, किसानों, युवाओं और रोजगार की तलाश में शहरों का रुख करने वाले परिवारों पर अत्यधिक बोझ डालने वाला है।

उन्होंने कहा कि जब प्रदेश की आर्थिक स्थिति चुनौतीपूर्ण है, रोजगार के अवसर सीमित हो रहे हैं और महंगाई आम लोगों की कमर तोड़ रही है, ऐसे समय में गाइडलाइन दरें बढ़ाना किसी भी रूप में न्यायसंगत नहीं है । इससे रियल एस्टेट, निर्माण कार्य, भवन निर्माण और इससे जुड़े हजारों श्रमिकों के रोजगार पर भी प्रतिकूल असर पड़ेगा। कन्हैया अग्रवाल ने स्पष्ट कहा कि सत्यमेव जयते फाउंडेशन इस जनविरोधी निर्णय का पुरजोर विरोध करेगा और इसे पूरी तरह गैरङ्कराजनीतिक जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि राजधानी में विभिन्न समाज संगठनों, युवा समूहों, महिला संगठनों और आम जनता की व्यापक भागीदारी के साथ आंदोलन होगा।प्रदेश के सभी जिलों में चरणबद्ध आंदोलन ,जिला मुख्यालयों में धरना, प्रदर्शन और ज्ञापन सौंपे जाएंगे । श्री अग्रवाल ने कहा कि हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से लाखों नागरिकों के हस्ताक्षर एकत्र कर राज्य सरकार को सौंपे जाएंगे , जनजागरण अभियान वार्डङ्कवार्ड जाकर गाइडलाइन बढ़ोतरी के प्रभाव और समाधान पर जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा । इसके साथ ही ऑनलाइन विरोध अभियान सोशल मीडिया के माध्यम से GuidelineWapsLo अभियान चलाया जाएगा ताकि हर तबके की आवाज सरकार तक पहुंचे।

श्री अग्रवाल ने कहा कि सत्यमेव जयते फाउंडेशन का एकमात्र उद्देश्य है कि आम जनता का हित सुरक्षित रहे । इसलिए सरकार से मांग की जाती है कि वह इस निर्णय को तुरंत वापस ले, गाइडलाइन दरों को पूर्ववत रखे और लोगों पर थोपे गए आर्थिक बोझ को खत्म करे । उन्होंने कहा कि यदि सरकार समय रहते सुनवाई नहीं करती, तो फाउंडेशन आंदोलन को और मजबूत व व्यापक रूप देगा। जनहित के लिए हर स्तर पर संघर्ष किया जाएगा और जनता के अधिकारों से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जाएगा।

कलेक्टर ने टेमरी अंतर्राज्यीय जांच चौकी के कर्मचारी साजिद मोहम्मद को लापरवाही बरतने किया निलंबित

महासमुंद। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के दौरान धान खरीदी प्रक्रिया में अवैध धान परिवहन एवं भंडारण पर रोक लगाने राज्य शासन द्वारा सख्त निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में टेमरी अंतर्राज्यीय जांच चौकी वन विभाग, तहसील बागबाहरा में पदस्थ कर्मचारी श्री साजिद मोहम्मद को लापरवाही और अनुशासनहीनता बरतने पर कलेक्टर श्री विनय लंगेह द्वारा निलंबित कर दिया गया है।।एवं विभागीय जांच हेतु संस्थित किया गया है।एस्मा के तहत यह कार्रवाई की गई है। अनुविभागीय अधिकारी बागबाहरा द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के अनुसार, जांच चौकी में स्थापित वाहन पंजी में आयातित वाहनों की प्रविष्टियाँ अव्यवस्थित पाई गईं। पंजी में वाहनों के संबंध में बिल/बिजक, मोबाइल नंबर तथा अन्य आवश्यक विवरण दर्ज नहीं किए गए थे। इस संबंध में दिए गए कारण बताओ नोटिस पर कर्मचारी साजिद मोहम्मद द्वारा प्रस्तुत जवाब भी अस्पष्ट एवं असंतोषजनक पाया गया। साथ ही संबंधित कर्मचारी ने धान के अवैध परिवहन को रोकने हेतु कलेक्टर (खाद्य शाखा) द्वारा जारी निर्देशों का पालन नहीं किया। इससे यह स्पष्ट हुआ कि कर्मचारी अपने कर्तव्य एवं दायित्वों के प्रति लापरवाह तथा अनुशासनहीन है। उल्लेखनीय है कि राज्य शासन ने धान खरीदी अवधि 15 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक सभी संलग्न कर्मचारियों पर छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम (श्वस्रूष्टङ्ग) 1979 लागू किया है, जिसके तहत कर्तव्यहीनता को अपराध माना गया है। साजिद मोहम्मद द्वारा इस अधिनियम का भी उल्लंघन पाया गया। इन्हीं तथ्यों को आधार मानते हुए कलेक्टर श्री विनय लंगेह ने कर्मचारी साजिद मोहम्मद भृत्य/चौकीदार, कृ.उ.म.स. बागबाहरा, टेमरी जांच चौकी को तात्कालिक प्रभाव से निलंबित कर विभागीय जांच के आदेश जारी किए हैं।

लोकशक्ति
www.lokshakti.in

संपादकीय

हर मोर्चे पर राष्ट्रवाद एवं देश-भक्ति आवश्यक

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान ने कॉरपोरेट सेक्टर से कहा है कि मुनाफा प्रेरित अपने कारोबार में वे कुछ राष्ट्रवाद एवं देश-भक्ति भी दिखाएं। जनरल चौहान कॉरपोरेट अधिकारियों के साथ एक सेमीनार में शामिल हुए। जनरल चौहान ने कहा कि कंपनियों को उत्पाद के देसी होने के संबंध में सच बोलना चाहिए। ऐसा हुआ है, जब कोई उत्पाद यह कह कर बेचा गया कि वह 70 प्रतिशत देसी है, मगर हकीकत में ऐसा नहीं था। सीडीएस के मुताबिक यह पहलू अहम है, क्योंकि इसका संबंध सुरक्षा से है। संभवतः उनका इशारा इस ओर था कि विदेशी उपकरणों के हैक होने या उनसे सूचनाएं उनके स्रोत देश में पहुंच जाने की आशंका रहती है। ऐसे उपकरणों का इस्तेमाल कंपनियां इसलिए करती हैं, क्योंकि वे किफायती पड़ती हैं।

हिंदी में शपथ : नए भारत की भाषाई चेतना का निर्णायक उद्घोष

ललित गर्ग
लेखक, पत्रकार, स्तंभकार

भारत के 53वें प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत द्वारा हिंदी में शपथ लेना भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में केवल एक औपचारिक घटना नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक, राष्ट्रीय और मनोवैज्ञानिक चेतना का नया शुभारंभ है। यह वह क्षण है जिसने भाषा को लेकर दशकों से चले आ रहे संकीर्ण विवादों, राजनीतिक विरोधाभासों और कृत्रिम विभाजनों पर एक गहरी चोट की है। हिंदी में शपथ का यह निर्णय राष्ट्रीय मानस में इस भावना को पुनः स्थापित करता है कि भाषा का प्रश्न केवल संचार का साधन नहीं, बल्कि राष्ट्र की आत्मा का प्रतीक है। यह निर्णय उस विरोधाभास पर भी प्रकाश डालता है जिसमें विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी को अपने ही देश में सबसे अधिक उपेक्षा, संकोच और राजनीतिक विरोध का सामना करना पड़ता रहा है।

भारत में भाषा सदैव राजनीति का एक सुविधाजनक औज़ार रही है। कुछ दशकों से चले आ रहे भाषाई आंदोलन और हिंदी-विरोधी राजनीति ने देश की एकता को अक्सर चुनौती दी है। क्षेत्रवाद की आड़ में कुछ राजनीतिक दलों ने हिंदी को एक क्षेत्र विशेष की भाषा बताकर उसका महत्व कम करने का प्रयास किया। लेकिन यह तर्क न तो व्यावहारिक था और न ही ऐतिहासिक। हिंदी किसी क्षेत्र की भाषा नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों के हृदय की भाषा है, जनमानस की अभिव्यक्ति है, भारत की आत्मा की धड़कन है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत द्वारा हिंदी में शपथ लेना इस सत्य को पुनः उद्घाटित करता है कि भारतीय लोकतंत्र की संवैधानिक संस्थाएँ केवल कानून और प्रशासन की रक्षा ही नहीं करतीं, बल्कि भारतीयता और राष्ट्रीय अस्मिता को भी नई दिशा देती हैं। यह कदम यह संदेश देता है कि नई पीढ़ी की संस्थाएँ अब संकोच नहीं, आत्मविश्वास के साथ भारत की भाषा में अपने कर्तव्यों की शुरुआत कर रही हैं।

हिंदी को लेकर जो विरोधाभास पैदा किया जाता रहा है, वह वास्तव में एक कृत्रिम एवं आग्रह-दुराग्रहपूर्ण द्वंद्व है। आज के वैश्विक दौर में भाषा का महत्व उसकी लोकस्वीकृति और उपयोगिता से तय होता है। हिंदी वैश्विक भाषाओं की सूची में तेजी से ऊपर बढ़ रही है। करीब 113 करोड़ के साथ अंग्रेजी पहले स्थान पर है. 111 करोड़ के साथ चीनी दुसरे स्थान पर है,इसके बाद हिन्दी का स्थान आता है। करीब 61.5 करोड़ विश्व में, हिन्दी को बोलने वाल लोगों की संख्या के आधार पर तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा का स्थान प्राप्त है। हिंदी का प्रभाव विश्व में बढ़ रहा है और यह सोशल मीडिया व संचार माध्यमों में भी लगातार उपयोग हो रही है। दुनिया भर के 175 से अधिक विश्वविद्यालयों में हिंदी भाषा पढ़ाई जा रही है। देवनागरी लिपि को दुनिया की सबसे वैज्ञानिक लिपियों में से एक माना जाता है। भारत सरकार की पहल के बाद से, संयुक्त राष्ट्र ने भी साप्ताहिक हिंदी समाचार बुलेटिन शुरू किया है। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, मोरिशस, दक्षिण अफ्रीका, खाड़ी देशों और यूरोप में हिंदी सीखने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। विश्व के कई विश्वविद्यालयों में हिंदी साहित्य, भाषाविज्ञान और अनुवाद अध्ययन का विस्तार हुआ है। हिंदी फिल्में, वेब प्लेटफॉर्म और मीडिया विश्व संस्कृति पर गहरा प्रभाव छोड़ रहे हैं। यह वह समय है जब हिंदी वैश्विक मंच पर उभर रही है, लेकिन अपने ही देश में उसे राजनीति और संकीर्णताओं का शिकार होना पड़ रहा है। यही वह असंगति है जिसे न्यायमूर्ति सूर्यकांत की शपथ ने बड़े सौम्य किंतु तीव्र संदेश के साथ उजागर किया है कि जब दुनिया हिंदी को सम्मान दे रही है तो भारत में उसकी उपेक्षा किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं हो सकती।

राष्ट्रीय प्रतीक केवल वस्तुएँ नहीं होते, वे राष्ट्र की चेतना के वाहक होते हैं। राष्ट्रध्वज केवल कपड़े का टुकड़ा नहीं, करोड़ों लोगों के स्वाभिमान और बलिदान का प्रतीक है। राष्ट्रगान केवल धुन नहीं, बल्कि भारत की समष्टिगत भावना का सूत्र है। उसी प्रकार राष्ट्र की भाषा-चाहे उसे हम राजभाषा कहें या राष्ट्रभाषा भारतीय पहचान और राष्ट्रीय एकता का अदृश्य धागा है। नए भारत का निर्माण तभी संभव है जब हम इन प्रतीकों का सम्मान केवल संविधान की धाराओं में नहीं, बल्कि हृदय में करें। हिंदी को लेकर जो संकोच, झिझक और कृत्रिम विरोध दशकों से बना हुआ था, वह राष्ट्रीय आत्मविश्वास के लिए बाधक था। हिंदी में शपथ लेकर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने इस मानसिक दरार को पाटने में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में हिंदी को वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित करने का साहसिक कार्य किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा से लेकर ब्रिक्स, जी-20 और अनेक अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उन्होंने हिंदी में संबोधन देकर दुनिया को यह संदेश दिया कि भारत अपनी भाषा को लेकर हिचकता नहीं, बल्कि गर्व करता है। इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने भी संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण देकर ऐतिहासिक परंपरा की शुरुआत की थी। उनकी वाणी में हिंदी केवल शब्द नहीं थी, बल्कि भारत की आत्मा की ध्वनि थी। नरेंद्र मोदी ने इस परंपरा को राष्ट्रीयता, आधुनिकता, आत्मविश्वास और वैश्विक उपस्थिति के साथ आगे बढ़ाया है। उन्हें यह समझ थी कि भाषा राष्ट्रीय चेतना की नींव होती है, और जिस राष्ट्र को विश्व नेतृत्व की आकांक्षा है, उसे अपनी भाषा पर गर्व करना ही होगा। जब राष्ट्र का प्रधानमंत्री अपनी भाषा को वैश्विक मंचों पर प्रतिष्ठा दिलाता है और जब राष्ट्र का प्रधान न्यायाधीश उसी भाषा में शपथ लेता है, तब यह संकेत मिलता है कि नए भारत की भाषा नीति संकोच नहीं, बल्कि स्वाभाविक भारतीयता की पुनर्स्थापना है।

हिंदी केवल भावनात्मक आग्रह नहीं है। यह शासन, न्याय, शिक्षा, प्रशासन, मीडिया और तकनीक की भाषा बनती जा रही है। डिजिटल इंडिया और नई तकनीकी क्रांति में हिंदी की भूमिका तेजी से बढ़ रही है। आज इंटरनेट पर सबसे तेजी से बढ़ने वाली भाषाओं में हिंदी शीर्ष पर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन अनुवाद और डिजिटल पत्रकारिता में हिंदी का उपयोग बढ़ाना भारत की ज्ञान-आर्थिक उन्नति के लिए अनिवार्य है। किसी भी राष्ट्र की प्रगति उसकी भाषाई आत्मनिर्भरता पर भी निर्भर करती है। जितनी अपनी भाषा मजबूत होगी, उतना ही विचार-निर्माण, नवाचार और जनसक्रियता मजबूत होगी। इस दृष्टि से हिंदी के प्रति उपेक्षा केवल सांस्कृतिक अपराध नहीं, बल्कि राष्ट्रीय विकास को बाधित करने वाला संकीर्ण एवं राष्ट्र-विरोधी दृष्टिकोण भी है।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत की हिंदी में शपथ वास्तव में एक वैचारिक उद्घोष है। यह घोषणा है कि भाषा को लेकर चलने वाला हमारा पुराना आत्मद्वंद्व समाप्त होना चाहिए। राष्ट्रभाषा का सम्मान किसी क्षेत्र या समुदाय पर थोपा हुआ बोझ नहीं, बल्कि वह प्राकृतिक बंधन है जो विविधता को सामूहिकता में बदलता है। यह वह बंधन है जो भारत को भारत बनाता है। यह वह अदृश्य शक्ति है जो उत्तर से दक्षिण, पश्चिम से पूर्व और ग्रामीण से महानगरीय भारत को एक सांस्कृतिक सूत्र में पिरोती है, व्यापार एवं विकास को गति देता है। हिंदी किसी पर थोपी जाने वाली भाषा नहीं, वह तो स्वयंस्फूर्त रूप से जनमानस की भाषा बन चुकी है। उसका विरोध अब एक राजनीतिक नाटक भर रह गया है जिसका वास्तविकता से कोई सरोकार नहीं। नए भारत ने अपने संकोचों को त्यागना शुरू कर दिया है। अपनी परंपराओं, अपने प्रतीकों और अपनी भाषा पर गर्व करना नया मानसिक स्वरूप बनता जा रहा है। न्यायपालिका से लेकर कार्यपालिका तक और वैश्विक मंचों से लेकर डिजिटल मंचों तक-हिंदी का सम्मान बढ़ रहा है। यह सम्मान न किसी के आदेश से आया है, न किसी दवाब से; यह सम्मान राष्ट्र की आत्मा से उठा है।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत की हिंदी में शपथ नए भारत की सांस्कृतिक स्वाधीनता का प्रतीक बन गई है। यह उस स्वाभिमान का उद्घोष है कि भारत अब अपनी भाषा से संकोच नहीं करेगा। यह वह क्षण है जिसने भाषा के प्रश्न को संवैधानिक गरिमा और राष्ट्रीय चेतना के सर्वोच्च स्तर पर स्थापित कर दिया है। इस कदम ने यह सिद्ध कर दिया है कि हिंदी केवल भाषा नहीं, बल्कि राष्ट्रीय आत्मा का प्रकाश है, एक ऐसा प्रकाश जो आत्मविश्वास, सांस्कृतिक प्रतिष्ठा और राष्ट्रीय एकता की नई राहें रोशन कर रहा है। यही वह दिशा है जिसमें नया भारत आगे बढ़ रहा है-अपनी भाषा में, अपने स्वभाव में और अपनी अस्मिता में आत्मविश्वास से भरपूर। **यह निजी विचार है।**

मोक्ष प्रदायनी है मोक्षदा एकादशी

पं. चन्द्रभूषण शुक्ला

हिंदू पंचांग के अगहन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस शुभ तिथि पर भगवान विष्णु व गीता जी की पूजा कर श्रीमद्भागवत गीता, विष्णु सहस्त्रनाम व पुरुष सूक्त का पाठ किया जाता है और गीता में दिए गए संदेशों को अपनाकर जीवन सफल बनाया जाता है।

संस्कृत भाषा के प्रचारक, साहित्यकार व धर्मशास्त्री पं. चन्द्रभूषण शुक्ला ने बताया कि हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशी होती हैं और जिस वर्ष में अधिकमास या मलमास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। मार्गशीर्ष मास के शुक्लपक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है और पुराणों के अनुसार यह व्रत शुभ फल एवं मोक्ष प्रदान करने वाला कहा गया है। मोक्षदा एकादशी व्रत पापों से मुक्ति और मृत्यु के बाद मोक्ष (मुक्ति) प्राप्त करने के लिए भगवान विष्णु की पूजा करने हेतु समर्पित एक शुभ तिथि है। साथ ही इस तिथि को ही गीता जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस एकादशी तिथि को मोक्षदायी तिथि भी कहा गया है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एकादशी पर मृत्यु को प्राप्त होने वाला व्यक्ति अपने पितरों के साथ उत्तम लोक में जाता है और उसकी आत्मा को शांति प्राप्त होती है तथा उसकी आत्मा को स्वतः ही पितरों की श्रेणी में स्थान मिल जाता है।

महामाया मन्दिर रायपुर के ज्योतिषी एवं भागवताचार्य पंडित मनोज शुक्ला ने बताया कि मोक्षदा एकादशी की पूजा में भगवान विष्णु को केले और पीली मिठाई का भोग लगाना चाहिए, इससे विष्णु जी प्रसन्न होते हैं और मनोकामना पूरी होती हैं। इसके अलावा थाली में पंचमेवा, फल, सिंघाडा, राजगीर के लड्डू, पंचामृत भी शामिल करना चाहिए।

मान्यता है कि पंचामृत का भोग लगाने से जातक को जल्द ही मनचाहा कैरियर प्राप्त होता है और रुके हुए काम पूरे होते हैं।

कथा - मोक्षदा एकादशी की कथा के अनुसार बहुत पहले गोकुल के राजा वैखानस ने एक रात सपने में अपने पिता को नरक में कष्ट भोगते देखा। इस पर उन्होंने विद्वानों और मुनि पर्वत से उपाय पूछा, जिन्होंने उन्हें मोक्षदा एकादशी का व्रत करने और उसका पुण्य अपने पिता को समर्पित करने की सलाह दी। राजा ने विधिपूर्वक व्रत किया, जिससे उनके पिता को नरक से मुक्ति मिली और वे स्वर्ग को प्राप्त हुए।

वैदिक पंचांग के अनुसार, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 30 नवंबर को रात 09 बजकर 29 मिनट पर शुरू हो रही है और अगले दिन यानी 01 दिसंबर को रात 07 बजकर 01 मिनट पर समाप्त होगा इसलिए 01 दिसंबर सोमवार को मोक्षदा एकादशी व्रत किया जाएगा।

एक राष्ट्रीय संकल्प: संपूर्ण सरकार और समाज साझा रूप से बाल विवाह मुक्त भारत की ओर अग्रसर

अन्नपूर्णा देवी

एक ऐसे देश में जहाँ महिलाएँ और बच्चे एक अरब से ज़्यादा जीवनों का आधार हैं, उनका सशक्तिकरण महज़ एक नीतिगत विकल्प नहीं है, बल्कि यह भारत की नियति का मार्ग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी शासन में, भारत एक ऐतिहासिक बदलाव के दौर से गुज़र रहा है, जो वैश्विक महत्वाकांक्षाओं को मानव-केंद्रित प्रगति के साथ जोड़ रहा है। नए भारत की कहानी केवल आर्थिक उपलब्धियों और बढ़ते वैश्विक कद में ही नहीं, बल्कि उन कक्षाओं में भी आकार ले रही है, जहाँ युवा मन विकसित होते हैं, उन आंगनवाड़ी केंद्रों में जहाँ हमारे बच्चों का पालन-पोषण होता है, और उन घरों में जहाँ आकांक्षाएँ पनपती हैं।

'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' के प्रति प्रधानमंत्री की अटूट प्रतिबद्धता, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के लिए एक मार्गदर्शक शक्ति बन गई है, जो विकसित भारत2047 के लिए हमारे सामूहिक मिशन को भी आगे बढ़ा रही है। इसी सफर में एक अहम पड़ाव पिछले वर्ष 27 नवंबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान शुरू हुआ है।

अपनी साहसिक और अटल दृष्टि के साथ, हमने वर्ष 2030 तक बाल विवाह को खत्म करने की अपनी राष्ट्रीय प्रतिबद्धता एक बार फिर दोहराई है, ताकि हर बालिका और बालक सुरक्षित रूप से बड़े हो सकें, अपनी शिक्षा जारी रख सकें और गर्व तथा आत्मविश्वास के साथ अपने भविष्य को आकार दे सकें। शुरू से ही, हमने 'संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज' के नज़रिए को अपनाया है, लिहाज़ा हम मानते हैं कि इस चुनौती का हल महज़ नीतियों से नहीं किया जा सकता। इसके लिए सामूहिक एकता की ज़रुरत है, जिसमें परिवार, समुदाय, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता, संस्थान और सरकार कंधे से कंधा मिलाकर, सदियों पुरानी प्रथा को तोड़ने और हर बच्चे की आकांक्षाओं की रक्षा करने के लिए एक साथ खड़े हों। हमारे साझा संकल्प के एक शक्तिशाली प्रतिबिंब के रूप में, गाँवों और कस्बों के करोड़ों लोग बाल विवाह को समाप्त करने का संकल्प लेने के लिए आगे भी आए हैं।

बाल विवाह मुक्त भारत के लिए 'पूरी सरकार' एकजुट

बाल विवाह हमारे देश में पीढ़ियों से चली आ रही सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। यह अक्सर उन समुदायों में दिखती है, जहाँ शिक्षा, संसाधनों और जागरूकता की सीमित पहुँच है। अभाव और असमान अवसरों के कारण पैदा हुई ये कमियाँ, इस प्रथा को जारी रखने में मदद करती हैं, जिससे अनगिनत बच्चे अपने उज्ज्वल भविष्य को साकार करने से वंचित रह जाते हैं।

वर्तमान में बेहतरी के लिए प्रयासः मोदी सरकार के तहत, हम उन जड़ों को खत्म कर रहे हैं, जिन्होंने कभी इस प्रथा को पोषित किया था। स्पष्ट नीतिगत दिशा, विचार विमर्श कर तैयार की गई योजनाओं और शासन में समुदायों के नए विश्वास के साथ, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय उन परिस्थितियों को खत्म करने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है, जिनके कारण बाल विवाह की प्रथा अब तक जारी रही। आज हम जो प्रगति देख रहे हैं, वह सुनियोजित ढंग से तैयार की गई योजनाओं की वजह से हैं, जिनके तहत महिलाएं और बच्चे राष्ट्रीय विकास के केंद्र में हैं।हमारी नीतियां और पहल, संवेदनशील कारणों को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई हैं। हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि हर अधिकार, देश के सबसे दूरस्थ गाँव और बस्तियों में सबसे कमजोर बच्चे के जीवन पर सकारात्मक असर डालते हुए अंतिम छोर तक पहुँचे। सरकार की हर योजना महिलाओं और बच्चों को जोखिम के हर चरण में सहारा देने के लिए तैयार की गई है, ताकि अजन्मे बच्चे से लेकर किशोरी तक, उनके जीवन के हर चरण की सुरक्षा, प्राथमिकता और सशक्तिकरण हो।

पोषण ट्रैकर और पोषण भी पढ़ाई भी से लेकर समग्र शिक्षा अभियान तक, और राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति कार्यक्रम से लेकर प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना तक, हर पहल एक सुरक्षा कवच और हर बच्चे के लिए एक सुरक्षित, सम्मानजनक और समान भविष्य की ओर एक मार्ग के रूप में कार्य करती है।

समावेशन के उत्प्रेरक के रूप में तकनीक की मदद से, मंत्रालय का प्रमुख डिजिटल प्लेटफॉर्म, पोषण ट्रैकर, 14 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों को स्तनपान कराने वाली माताओं, छह साल से कम उम्र के बच्चों और किशोरियों से सहजता से जोड़ता है। इसने देश भर में 10.14 करोड़ से अधिक लाभार्थियों के लिए एक मज़बूत सुरक्षा तंत्र तैयार कर दिया है। इस डिजिटल सक्षमता के साथ पोषण भी पढ़ाई भी, एक बदलावकारी प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा पहल के रूप में तैयार हुआ है, जो यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक पूर्व-प्राथमिक बच्चे को समग्र, उच्च-गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक प्रोत्साहन मिले, जो आजीवन सीखने की भावना की नींव रखता है।

हमारी नीतियाँ न केवल इरादे, बल्कि ज़मीनी स्तर पर कार्रवाई को भी दर्शाती हैं। निरंतर बजटीय प्रतिबद्धताओं और लक्षित निवेशों में सुधारों को शामिल करते हुए, मोदी सरकार ने यह साफ कर दिया है कि बाल विवाह जैसी गंभीर समस्याओं से बच्चों की रक्षा करना एक राष्ट्रीय प्राथमिकता बनी हुई है। राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति कार्यक्रम, जिसके लिए केवल 2025-26 के लिए 1,827 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी बच्चा गरीबी के कारण स्कूल न छोड़े, जो बाल विवाह के सबसे अहम कारणों में से एक है। इस बीच, प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली युवतियों को ज़रुरी वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ने युवाओं को उद्योग-संबंधित कौशल से लैस करके, उन्हें वित्तीय प्रोत्साहन और मान्यता प्राप्त सरकारी प्रमाणन प्रदान करके इस सुरक्षा कवच को और मज़बूत किया है। इसी प्रकार, प्रधानमंत्री-दक्ष योजना, हाशिए पर पड़े समुदायों, खासकर अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के युवाओं को सशक्त बनाती है, जो बाल विवाह के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील हैं। उन्हें कौशल और अवसरों का लाभ देकर, हम समृद्ध और स्वतंत्र जीवन के मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नई मिसाल कायम कर रहे हैं।

प्रभावः बाल विवाह मुक्त भारत बनने के और नज़दीक

कुछ साल पहले तक, बाल विवाह को समाप्त करने का विचार दूर की कौड़ी, यहाँ तक कि असंभव नज़र आता था। लेकिन भारत ने इसके विपरीत साबित कर दिया है। स्पष्ट नीतियों, निरंतर कार्रवाई, केंद्रित जमीनी प्रयासों और मापयोग्य प्रगति के ज़रिए, हमने उस धारणा को चुनौती दी है और दिखाया है कि बदलाव न केवल मुमकिन है, बल्कि पहले से ही उसके प्रयास जारी हैं।

यह अभूतपूर्व बदलाव हज़ारों छोटी-बड़ी, सशक्त कोशिशों का नतीजा है। हमारे बाल विवाह निषेध अधिकारी (सीएमपीओ) इस मिशन की रीढ़ बनकर उभरे हैं। पिछले एक साल में ही, हमने देश भर में 37,000 से ज़्यादा सीएमपीओ नियुक्त करके अपनी अग्रिम पंक्ति को मज़बूत किया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सक्षम बनाकर, पंचायतों को सशक्त बनाकर और जिला प्रशासन को बाल संरक्षण कानूनों की जानकारी देकर, हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि सबसे वंचित परिवारों को भी सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाए, बच्चों को वापस स्कूल लाया जाए और समुदायों को बाल विवाह के गंभीर उल्लंघन के बारे में जागरूक किया जाए।

अब तक, हमने 6,30,000 से ज़्यादा, स्कूल न जाने वाली लड़कियों की पहचान की है और उन्हें कक्षाओं में फिर से दाखिला दिलाया है।

चुप्पी से लेकर शिकायत तक, सामाजिक कलंक से लेकर समर्थन तक-भारत ने चुना बदलाव का रास्ताः आज, हम इस समस्या का हल अधिक सटीकता, पारदर्शिता और प्रभाव के साथ निकालने के लिए नवीनतम तकनीकी प्रगति की मदद ले रहे हैं। सार्वजनिक रूप से सुलभ, केंद्रीकृत मंच, बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल, इस प्रगति का प्रतीक है, जो देश भर के बाल विवाह निषेध अधिकारियों की जानकारी एक साथ लाता है, मामलों की रिपोर्टिंग के लिए एक प्रभावी तंत्र प्रदान करता है, और हितधारकों और नागरिकों के बीच जागरूकता को मज़बूत करता है।

पहली बार, बाल-विवाह-मुक्त भारत का सपना एक एकीकृत राष्ट्रीय मिशन के रूप में विकसित हुआ है। भारत सरकार का प्रत्येक अंग और समाज का प्रत्येक वर्ग इस साझा उद्देश्य और दृढ़ संकल्प के साथ मिलकर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में, हम आज न केवल अपने बच्चों की सुरक्षा कर रहे हैं, बल्कि विकसित भारत की एक मज़बूत, आत्मविश्वासी और सशक्त नींव भी रख रहे हैं।

जैसे-जैसे भारत बाल विवाह के खिलाफ अपनी सामूहिक लड़ाई में एक निर्णायक मोड़ पर पहुँच रहा है, हम दुनिया के सामने एक नया मॉडल पेश कर रहे हैं, कि कैसे शासन और समुदाय मिलकर हर बच्चे की सुरक्षा के लिए काम कर सकते हैं और बाल विवाह के वैश्विक संकट को तत्काल और निश्चित रूप से खत्म कर सकते हैं। आखिरकार, ये बच्चे ही उस विकसित भारत के पथप्रदर्शक और सच्चे 'सारथी' हैं, जिसका निर्माण हम सभी करना चाहते हैं।श

यह निजी विचार है।

विकसित भारत' का गुमशुदा आधा हिस्साः भारत की विकास संबंधी रणनीति के रूप में श्रम संहिताओं का महत्व

आरती आहूजा तथा कार्तिक एमपी

वर्ष 2047 तक भारत को 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए श्रमबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना अनिवार्य है। फिलहाल श्रमबल में महिलाओं की भागीदारी 41.7 प्रतिशत है और विकसित भारत का लक्ष्य इसे बढ़ाकर 70 प्रतिशत तक ले जाना है। लगभग 30-अंकों के इस अंतराल को पाटने का मूल मकसद राष्ट्रीय उत्पादकता को बढ़ाना तथा यह सुनिश्चित करना है कि भारत की विकास गाथा को सिर्फ आधे लोग ही नहीं, बल्कि सभी लोग आकार दें। शिक्षा, डिजिटल सुलभता और उद्यमिता के मामले में हुई प्रगति के बावजूद, अभी भी बहुत सी संभावनाओं का दोहन बाकी है। भारत को एक ऐसा श्रम इकोसिस्टम तैयार करना होगा जो महिलाओं को प्रवेश करने, टिके रहने तथा आगे बढ़ने में समर्थ बनाए और भारत के एकीकृत श्रम संहिताओं का कार्यान्वयन इन प्रणालीगत बाधाओं को दूर करने और समावेशन को उत्पादकता में बदलने का एक दुर्लभ मौका देता है।

जरा गौर करें - ई-श्रम पर पंजीकृत सीता नाम की उत्तर प्रदेश की एक श्रमिक बच्चों की देखभाल की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होने के चलते अपने दो बच्चों का पालन-पोषण करते हुए, घर बैठकर एक ठेकेदार के लिए कपड़े सिलती है। इससे उसे एक अनियमित आय होती है। उनके जैसी महिलाओं के लिए, नई श्रम संहिताएं एक बड़ा परिवर्तनकारी कदम साबित हो सकती हैं। पास की एक कपड़ा फैक्ट्री अब औपचारिक अनुबंधों के साथ अलग-अलग पालियों में काम करने के लिए महिलाओं की भर्ती कर रही है। पहली बार, भारत के श्रम कानूनों का ढांचा सीता जैसी लाखों महिलाओं के लिए बाधक होने के बजाय उनका संबल बनने के लिए तैयार है।

वर्ष 2019 और 2020 के बीच अधिनियमित श्रम संहिताएं 29 बिखरे कानूनों को चार सुव्यवस्थित ढांचों - मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा, पेशेगत सुरक्षा और औद्योगिक संबंध संहिताओं - में समेकित करती हैं। यह विधायी मंशा साहसिक है और अब अनेक राज्य तेजी से इन्हें लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। भारत के पास इस मंशा को प्रभाव में बदलने का एक महत्वपूर्ण मौका है और यह प्रभाव कुछ इस किस्म का है।

सामाजिक सुरक्षाः पहले कदम के रूप में दृश्यता

सामाजिक सुरक्षा संहिता मातृत्व, स्वास्थ्य बीमा, पेंशन और बच्चों की देखभाल से जुड़े पहलुओं को शामिल करते हुए गिग और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की स्थापना करती है। ई-श्रम पोर्टल पर 30.6 करोड़ से अधिक श्रमिक पंजीकृत हैं, जिनमें से 53 प्रतिशत यानी 16 करोड़ महिलाएं हैं। इस पोर्टल और आधार आधारित यूएएन के बीच का जुड़ाव (लिंकेज) इन हकों को किसी भी स्थान पर और किसी भी क्षेत्र (सेक्टर) में दिलाया जाना संभव बनाता है। यह बुनियादी ढांचा बच्चे के जन्म या देखभाल जैसे जीवन के प्रमुख बदलवों के दौरान होने वाली क्षति को कम कर सकता है।

दृश्यता तो महज पहला कदम भर है। पंजीकरण को कल्याणकारी वितरण प्रणालियों से जोड़ने की प्रक्रिया में तेजी लाई जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि महिलाओं के पास सिर्फ पहचान पत्र ही नहीं हो, बल्कि उन्हें वास्तविक सहायता भी मिले। इससे महिलाओं को उनके रोजगार चक्र में सुरक्षित व टिकाए रखने के तौर-तरीकों को नए सिरे से परिभाषित किया जा सकेगा।

आर्थिक अवसंरचना के रूप में देखभाल

किसी भी महिला से अगर नौकरी छोड़ने की वजहों के बारे में पूछिए, तो अक्सर एक ही जवाब मिलेगा - बच्चों की देखभाल। पेशेगत सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कामकाज की स्थिति से संबंधित संहिता इसी समस्या से निपटती है। यह देश के लगभग 62 प्रतिशत श्रमिकों को रोजगार देने वाले सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के समूहों को संयुक्त रूप से क्रेच स्थापित करने, देखभाल की लागत को वितरित करने और इसे अनुपालन संबंधी बोझ से हटकर एक सक्षमकारी आर्थिक अवसंरचना में परिवर्तित करने में सक्षम बनाती है। राज्यों को अब उद्योग संघों के साथ मिलकर इन क्रेचों को बड़े पैमाने पर संचालित करना होगा। विशेष रूप से औद्योगिक गलियारों और एसईजेड में, ताकि किसी भी मां को नौकरी और अपने बच्चे की देखभाल के बीच चुनना न पड़े। **यह निजी विचार है।**

उत्तर प्रदेश ने भारत समुद्री सप्ताह 2025 में प्रमुख समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करके अंतर्देशीय जलमार्गों के विस्तार में तेजी लाई

आईडब्ल्यूएआई ने गंगा (एनडब्ल्यू 1) में अंतर्देशीय जलमार्ग के विस्तार हेतु 6,000 करोड़ रुपये से अधिक के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए

आईडब्ल्यूएआई ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एनडब्ल्यू1 पर नए क्रूज जहाजों, जहाज मरम्मत सुविधा और इलेक्ट्रिक चार्जिंग अवसंरचना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

वाराणसी में दो नए रिवर क्रूज टर्मिनल और एक क्षेत्रीय उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित किए जायेंगे

हेरिटेज रिवर जर्नीज और अलकनंदा क्रूज, आईडब्ल्यूएआई तथा उत्तर प्रदेश सरकार के साथ साझेदारी में एनडब्ल्यू-1 पर क्रूज परिचालन का विस्तार करेंगे

पीआईबी

देश में जलमार्गों के विकास से संबंधित पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएसडब्ल्यू) के अंतर्गत नोडल एजेंसी भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) ने उत्तर प्रदेश के अंतर्देशीय जलमार्ग नेटवर्क के विकास एवं विस्तार हेतु बड़ी घोषणाएं कीं और भारत समुद्री सप्ताह 2025 (आईएमडब्ल्यू) में प्रमुख समझौतों पर हस्ताक्षर किए। आईडब्ल्यूएआई ने गंगा नदी (एनडब्ल्यू1) में अंतर्देशीय जलमार्ग नेटवर्क के विकास और विस्तार हेतु 6,000 करोड़ रुपये से अधिक के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए।

इन समझौता ज्ञापनों का उद्देश्य राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (गंगा) पर नदी क्रूज पर्यटन, जहाज मरम्मत अवसंरचना, मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी और स्वच्छ ऊर्जा परिवहन को मजबूत करना है। आईडब्ल्यूएआई ने आईएमडब्ल्यू 2025 के दौरान इन समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर के बाद, उत्तर प्रदेश में अंतर्देशीय जल परिवहन और नदी क्रूज अवसंरचना को गति देने हेतु 1,350 करोड़ रुपये के निवेश को बढ़ावा देने की घोषणा की है।

अंतर्देशीय जलमार्ग के विकास को बढ़ावा देने से संबंधित राष्ट्रव्यापी प्रयासों के तहत, जिसमें 25 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए, उत्तर प्रदेश ने वाराणसी और गंगा गलियारे में परिचालन के विस्तार पर केन्द्रित प्रमुख प्रतिबद्धताएं हासिल कीं। आईडब्ल्यूएआई ने नए क्रूज जहाजों के विकास एवं उन्हें बेड़े में शामिल करने और राष्ट्रीय जलमार्गों पर क्रूज पर्यटन का विस्तार करने हेतु हेरिटेज रिवर जर्नीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। अलकनंदा क्रूज के साथ एक अन्य समझौते से एनडब्ल्यू-1 पर क्रूज जहाजों के परिचालन में सहायता मिलेगी, जिससे वाराणसी में प्रीमियम नदी पर्यटन और हेरिटेज सर्किट को बढ़ावा मिलेगा। इनके लिए कुल 800 करोड़ रुपये से अधिक की राशि निर्धारित की गई है।

उत्तर प्रदेश को एक क्षेत्रीय समुद्री सेवा केन्द्र के रूप में स्थापित करने की उम्मीद के साथ, आईडब्ल्यूएआई ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ वाराणसी में एक नए जहाज मरम्मत केन्द्र के विकास हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह केन्द्र 350 करोड़ रुपये के निवेश से महत्वपूर्ण अवसंरचना और उपयोगिता संबंधी सहायता प्रदान करेगा। वाराणसी में 200 करोड़ रुपये के निवेश से दो नए रिवर क्रूज़ टर्मिनल भी विकसित किए जायेंगे। इससे भारत के सबसे तेजी से बढ़ते क्रूज पर्यटन स्थलों में से एक, वाराणसी में यात्रियों की सुविधाओं और परिचालन क्षमता में सुधार होगा।

केन्द्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि ये समझौते अपनी नदी प्रणालियों के आधुनिकीकरण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। श्री सोनोवाल ने इस कदम को भारत के समुद्री भविष्य के लिए एक परिवर्तनकारी क्षण बताते हुए कहा, ÷ये समझौता ज्ञापन यह दर्शाते हैं कि कैसे अंतर्देशीय जलमार्ग विकास, पर्यटन और क्षेत्रीय एकीकरण के इंजन के रूप में उभर रहे हैं।÷

स्वच्छ और सतत नदी परिवहन को बढ़ावा देने हेतु, राज्य ने भारत के राष्ट्रीय हरित नौवहन मिशन और कम उत्सर्जन वाले नदी परिवहन के दृष्टिकोण के अनुरूप इलेक्ट्रिक पोत चार्जिंग अवसंरचना के लिए एक परियोजना को मंजूरी दी है। कुल 100 करोड़ रुपये के इस समझौता ज्ञापन से जहाजों के लिए इलेक्ट्रिक चार्जिंग अवसंरचना की शुरुआत संभव होगी, जो राष्ट्रीय हरित नौवहन मिशन का समर्थन करेगी।

सर्बानंद सोनोवाल ने आगे कहा, ÷हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में शुरू की गई परिवर्तनकारी नीतियों के परिणामस्वरूप, 2014 से आईडब्ल्यूटी क्षेत्र व्यापार और परिवहन के मामले में अभूतपूर्व वृद्धि का साक्षी बना है। इसी क्रम में, ये समझौता ज्ञापन समावेशी, सतत और प्रौद्योगिकी-संचालित विकास सुनिश्चित करते हुए विश्वस्तरीय जलमार्ग अवसंरचना के निर्माण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं। प्रत्येक समझौता 2047 तक भारत को एक वैश्विक समुद्री केन्द्र बनाने के हमारे लक्ष्यों के अनुरूप है।÷

वाराणसी में एक क्षेत्रीय उत्कृष्टता केन्द्र (आरसीओई) की स्थापना के लिए 200 करोड़ रुपये की एक और पहल कौशल विकास पर केन्द्रित है। यह नया आरसीओई अंतर्देशीय जल परिवहन संचालन, पोत डिजाइन एवं हरित प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान, कौशल प्रशिक्षण और नवाचार को बढ़ावा देगा। रेनस लॉजिस्टिक्स के साथ 1,000 करोड़ रुपये के एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन से गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों पर आधुनिक टग-बार्जों को शामिल करना संभव हो सकेगा। इससे माल परिवहन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

जिले के 75 अमृत सरोवरों में मनाया गया संविधान दिवस स्थानीय बोली में प्रस्तावना का पाठन

सुकमा, एजेंसी। कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव के निर्देश एवं जिला पंचायत सीईओ मुकुंद ठाकुर के मार्गदर्शन में जिले के 75 निर्मित अमृत सरोवरों में संविधान दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। मनरेगा योजना के तहत राज्य कार्यालय से जारी निर्देशों के अनुरूप आयोजित इस कार्यक्रम में स्थानीय बोली और भाषा में संविधान प्रस्तावना का सामूहिक पाठ किया गया। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों को संविधान में निहित मौलिक कर्तव्यों, अधिकारों और मूल्यों की जानकारी दी गई। साथ ही जल संरक्षण, वृक्षारोपण, अमृत सरोवरों की स्वच्छता एवं सुरक्षा बनाए रखने की सामूहिक शपथ दिलाई गई। जिला प्रशासन ने इसे जनभागीदारी और जागरूकता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया।

भारत-यूएई ने तीसरी सीईपीए संयुक्त समिति की बैठक बुलाई; द्विपक्षीय व्यापार 100 अरब डॉलर के पार

पीआईबी

भारत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने नई दिल्ली में भारत-यूएई सीईपीए (व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता) के अंतर्गत संयुक्त समिति की तीसरी बैठक सफलतापूर्वक आयोजित की। बैठक की सह-अध्यक्षता वाणिज्य विभाग के अपर सचिव श्री अजय भादू और यूएई के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कार्य सहायक अवर सचिव जुमा अल कैत ने की। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार में हुई तीव्र वृद्धि का स्वागत किया, जो वित्त वर्ष 2024-25 में 100.06 अरब अमेरिकी डॉलर को पार कर गया। यह 19.6 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है और भारत के प्रमुख व्यापारिक भागीदारों में से एक के रूप में यूएई की स्थिति की पुष्टि करता है। भारत-यूएई संयुक्त आयोग द्विपक्षीय व?यापार में प्रगति की समीक्षा, चुनौतियों का समाधान और सीईपीए को लागू करने के लिए प्राथमिक संस्थागत तंत्र के रूप में कार्य करता है।

दोनों पक्षों ने सीईपीए के अंतर्गत प्रगति की व्यापक समीक्षा की। इसके साथ ही बाजार पहुंच के मुद्दों, डेटा साझाकरण, गोल्ड टीआरक्यू के आवंटन, एंटी-डंपिंग मामलों, सेवाओं, उत्पत्ति के नियमों, बीआईएस लाइसेंसिंग आदि पर विस्तृत चर्चा की गई।

भारतीय पक्ष ने पारदर्शी प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से गोल्ड टीआरक्यू आवंटित करने के अपने हालिया निर्णय के बारे में भी यूएई को जानकारी दी।

दोनों पक्षों ने हाल ही में हुई उच्च-स्तरीय बैठकों की समीक्षा की, जिनमें वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश व्यापार मंत्री डॉ. थानी बिन अहमद अल ज़ायौदी के बीच मुंबई और दुबई में हुई बैठकें शामिल हैं। उन्होंने वर्ष 2030 तक गैर-तेल/गैर-कीमती धातु व्यापार को 100 अरब डॉलर तक बढ़ाने के लक्ष्य की ओर अपनी साझा प्रतिबद्धता दोहराई। चर्चाओं में फार्मास्यूटिकल्स में नियामक सहयोग, उत्पत्ति प्रमाणपत्रों (वह आधिकारिक दस्तावेज़, जो यह प्रमाणित करता है कि किसी उत्पाद का निर्माण किस देश में हुआ है) से संबंधित मुद्दों का समाधान, बीआईएस समन्वय तथा कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), भारत और जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण मंत्रालय (एमओसीसीएई), संयुक्त अरब अमीरात के बीच खाद्य सुरक्षा एवं तकनीकी आवश्यकताओं पर समझौता ज्ञापन पर शीघ्र हस्ताक्षर शामिल थे।

बैठक का समापन दोनों पक्षों के बीच व्यापार सुगमता, नियामक सहयोग, डेटा साझाकरण को मज़बूत करने और सेवा उपसमिति की बैठक आयोजित करने पर सहमति के साथ हुआ। यूएई प्रतिनिधिमंडल ने वाणिज्य सचिव श्री राजेश अग्रवाल के साथ भी बैठक की, जहां दोनों पक्षों ने सीईपीए के अधिकतम उपयोग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। यूएई प्रतिनिधिमंडल की यह यात्रा व्यापार संतुलन को मज़बूत करने, बाज़ार के अवसरों का विस्तार करने और सीईपीए के तहत रणनीतिक साझेदारी को और मज़बूत करने की दोनों देशों की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

समन्वित प्रयासों से यह सुनिश्चित होगा कि मिशन मौसम के लक्ष्य समय से पहले प्राप्त हो जाएं: डॉ. जितेंद्र सिंह

डॉ. जितेंद्र सिंह ने समय-सीमा में तेजी लाने का आग्रह किया क्योंकि यह स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा घोषित एक प्रमुख कार्यक्रम है

पीआईबी

केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने महत्वाकांक्षी 'मिशन मौसम' पहल के अंतर्गत खरीद और स्थापना गतिविधियों की चल रही प्रगति का आकलन करने के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) में एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने संबंधित अधिकारियों से समय-सीमा में तेजी लाने को कहा क्योंकि यह एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसकी घोषणा स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने की थी।

बैठक में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव डॉ. एम. रविचंद्रन के साथ मंत्रालय और भारत मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और वैज्ञानिक भी

उपस्थित थे। अधिकारियों ने देश में शुरू की जा रही विभिन्न अवलोकन और रडार प्रणालियों की चल रही खरीद, बुनियादी ढांचे की तैयारी और त्वरित स्थापना समय-सीमा की विस्तृत स्थिति प्रस्तुत की।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र को समर्पित मिशन मौसम, भारत की मौसम पूर्वानुमान और जलवायु निगरानी क्षमताओं में प्रगति है। उन्होंने कहा कि पूर्व चेतावनी प्रणालियों को मज़बूत करने, आपदा तैयारी को बेहतर बनाने और अधिक सटीक, स्थान-विशिष्ट पूर्वानुमान प्रदान करने के लिए खरीद और स्थापना गतिविधियों का समय पर क्रियान्वयन अत्यंत महत्वपूर्ण है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने भारत मौसम विज्ञान विभाग और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि खरीद प्रक्रियाएं पारदर्शी, कुशल और वैश्विक बेहतर प्रणालियों के अनुरूप बनी रहें। उन्होंने प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में स्थापनाओं को तेज़ करने और क्षेत्र-स्तरीय प्रगति की निगरानी के लिए उन्नत ट्रैकिंग प्रणाली अपनाने का भी आह्वान किया। डॉ. सिंह ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत मौसम विज्ञान विभाग और मंत्रालय के बीच समन्वित प्रयासों से मिशन मौसम के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्राप्त कर लिया जाएगा।

केंद्र ने सीएसआईसी 1.0 किया लॉन्च, भारत के साइबर सिक्योरिटी इकोसिस्टम को बनाएगा मजबूत

नई दिल्ली । इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, भारत के साइबर सिक्योरिटी इकोसिस्टम को मजबूत करने की एक ऐतिहासिक पहल के रूप में इंफोर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन एंड अवेयरनेस (आईएसईए) प्रोजेक्ट के तहत साइबर सिक्योरिटी इनोवेशन चैलेंज (सीएसआईसी) 1.0 लॉन्च किया गया है।

एमईआईटीवाई के सचिव एस कृष्णन ने कॉन्सेप्ट वीडियो, वेबसाइट और रजिस्ट्रेशन पोर्टल और सीएसआईसी 1.0 की रूल बुक को पेश किया। एस कृष्णन ने दो-आयामी राष्ट्रीय साइबर सिक्योरिटी रणनीति की आवश्यकता पर बल देते हुए उभरते खतरों के बारे में जागरूकता और टेक्नोलॉजिकल क्षमताओं को मजबूत करने की बात की। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि सीएसआईसी 1.0 दोनों अनिवार्यताओं को संबोधित करता है। यह पहल छात्रों को वास्तविक दुनिया की साइबर सिक्योरिटी चुनौतियों से अवगत करवाती है। यह न केवल स्किल्ड प्रोफेशनल्स का निर्माण करती है और साइबर सिक्योरिटी को एक व्यवहार्य करियर पथ के रूप में स्थापित करती है, बल्कि होमग्रोन, प्रोडक्ट-ऑरिएंटेड सॉल्यूशन को भी कैटैलाइज करती है, जो भारत की साइबर सिक्योरिटी को मबूत करते हैं। डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के सीईओ विनायक गोडसे ने इस बात पर प्रकाश डाला कि अपनी तरह की यह अनूठी पहल छात्रों और शोधकर्ताओं को शुरुआती दौर से ही इनोवेशन करने और उद्यमशीलता की मानसिकता विकसित करने में सक्षम बनाती है।

खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की विभागीय समीक्षा बैठक सम्पन्न

नवीन खादी शोरूम, तिरंगा उत्पादन, बांस मिशन प्रशिक्षण तथा रोजगार सृजन कार्यक्रमों की समीक्षा

रायपुर, लोकशक्ति

छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की विभागीय समीक्षा बैठक 27 नवंबर 2025 को माननीय अध्यक्ष श्री राकेश पांडेय की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में प्रबंध संचालक श्री पी.एस. एल्मा सहित वरिष्ठ अधिकारियों और जिला अधिकारियों ने भाग लिया। प्रबंध संचालक ने विभागीय योजनाओं की प्रगति, उत्पादन, विपणन, वित्तीय स्थिति और आगामी कार्ययोजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की। इसके पश्चात अध्यक्ष और प्रबंध संचालक द्वारा महत्त्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए गए।

बैठक में दुर्ग जिले में नए खादी शोरूम की स्थापना, खादी से राष्ट्रीय ध्वज (तिरंगा) निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत, तथा बांस मिशन के अंतर्गत युवाओं एवं महिलाओं को प्रशिक्षण कार्यक्रमों से जोड़ने के निर्णय लिए गए। साथ ही प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की समीक्षा की गई। उत्पादन इकाइयों, विक्रय केंद्रों एवं स्टॉक उपलब्धता का भी विस्तार से आकलन किया गया।

प्रबंध संचालक ने निर्देशित किया कि जिला कार्यालय योजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति की नियमित समीक्षा सुनिश्चित करें। उत्पादन इकाइयों में गुणवत्ता नियंत्रण, समयबद्ध उत्पादन तथा उत्पादों के विपणन, ब्रांडिंग और पैकेजिंग को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। बांस मिशन सहित अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों को मैदानी स्तर पर प्रभावी रूप से लागू करने और अधिकारियों-कर्मचारियों की कार्यकुशलता एवं उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। अध्यक्ष श्री राकेश पांडेय ने कहा कि खादी और ग्रामोद्योग ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाते हैं और आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़ की दिशा में एक मजबूत साधन हैं। उन्होंने युवाओं और महिलाओं की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने, आधुनिक तकनीक अपनाने तथा विपणन नेटवर्क के विस्तार पर बल दिया।

आईएनएस सह्याद्री स्टील्थ फ्रिगेट ने फिलीपींस में अपनी तैनाती के हार्बर फेज़ के लिए मनीला में पोर्ट कॉल करने से पहले फिलीपींस नेवी के साथ एक एक्सरसाइज़ की।

लोकशक्ति
www.lokshakti.in

लायंस क्लब चांपा ने मनाया 60 वाँ स्थापना दिवस

जांजगीर चांपा /

लायंस क्लब चांपा ने क्लब का 60 वाँ स्थापना दिवस मनाया है। लायंस क्लब चांपा की स्थापना 26 नवंबर 1965 को हुई थी । संस्थापक सदस्यों ने सेवा भावना एवं जरूरत मंद लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य को लेकर अंतरराष्ट्रीय संस्था लायंस क्लब की स्थापना की थी साथ ही शहर में प्रथम अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय की शुरुवात की थी जो आज अनवरत रूप से संचालित है जिसमें 1400 से भी अधिक विद्यार्थी अध्ययन कर रहे है । लायंस क्लब इंटरनेशनल, डिस्ट्रिक्ट एवं नगर में चांपा क्लब की अपनी एक अलग पहचान है लायंस क्लब एक मात्र ऐसी संस्था है जिसके द्वारा किसी अन्य शासकीय अर्ध शासकीय , निजी संस्था निकाय इत्यादि से कोई अनुदान नहीं लिया जाता बल्कि लायन सदस्य ही समस्त खर्च वहन कर सेवा गतिविधि को अंजाम देते है , नगर में मानवता की सेवा से संबंधित जो भी कार्य होते है उसमें क्लब की निश्चित भागीदारी होती है इसके लिए क्लब हमेशा अग्रणी रहता है। क्लब के सदस्य धर्म , जाति, ऊंच ,नीच , राजनैतिक भेद भाव से दूर रहकर समान रूप से पीड़ित मानवता की सेवा करते है ।

स्थापना दिवस के अवसर पर क्लब के द्वारा समारोह का आयोजन बैरियर रोड चांपा स्थित होटल सुमित इन के सभागार में की गई इस अवसर पर क्लब के द्वारा डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन विजय अग्रवाल जी की आधिकारिक यात्रा का आयोजन भी किया गया । कार्यक्रम के शुरुवात में क्लब के अध्यक्ष लायन संतोष कुमार सोनी, सचिव लायन राजेश अग्रवाल, विशिष्ट अतिथि पूर्व प्रांतपाल लायन डॉ व्ही के अग्रवाल, डिस्ट्रिक्ट कैबिनेट सचिव लायन बी के सिंह , डिस्ट्रिक्ट कैबिनेट ट्रेजरार लायन कैलाश अग्रवाल मुख्य अतिथि डिस्ट्रिक्ट गवर्नर श्रद्धद्धद्ध लायन विजय अग्रवाल जी मंचस्थ हुवे और लायंस क्लब के संस्थापक मेलविन जोन्स की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर तथा मां सरस्वती की पूजा अर्चना कर कार्यक्रम की शुरुवात की क्लब अध्यक्ष के समारोह प्रारंभ करने की घोषणा के बाद क्लब सचिव लायन राजेश अग्रवाल ने ध्वज वंदन किया , क्लब अध्यक्ष ने स्वागत भाषण दिया तथा क्लब के सदस्यों ने मंचस्थ अतिथियों का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया । क्लब सचिव ने प्रशासनिक एवं सेवा गतिविधि संबंधी प्रतिवेदन का पठन किया एवं डिस्ट्रिक्ट गवर्नर जी को मिनट्स रजिस्टर , स्लेबबुक का निरीक्षण कराया । पोजेक्टर के माध्यम से क्लब के स्वागति विधिओं का डिजिटल प्रदर्शन किया गया ।

मंचस्थ अतिथियों ने समारोह को संबोधित करते हुवे क्लब के सेवागतिविधि की प्रशंसा की । लायन विनोद कुमार अग्रवाल ने डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के जीवन का संक्षिप्त परिचय दिया ।

मुख्य अतिथि डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन विजय अग्रवाल ने अपने संबोधन में क्लब की सदस्यता वृद्धि पर जोर देते हुवे इंटरनेशनल के मिशन 1.5 को पूरा करने एवं सदस्यों से अधिक से अधिक दान देने का आग्रह किया । कार्यक्रम में लायन क्लब के सभी प्रमुख सदस्य ने उपस्थित रहकर कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सहयोग दिया ।

जगह-जगह पर नगर वासियों ने किया बारातियों का स्वागत

जांजगीर चांपा / अगहन सुदी शुक्ल पक्ष पंचमी को शिवरीनारायण मठ में भगवान राघवेंद्र सरकार और माता सीता का विवाह महोत्सव अत्यंत श्रद्धा भक्ति के साथ संपन्न हुआ। नर- नारायण मंदिर के सामने भगवान का दिव्य रथ सजाया गया। भगवान राघवेंद्र सरकार, माता जानकी एवं लक्ष्मण जी की मूर्तियां विराजित कर शंख ध्वनि, विजयघंट,घंटी, मृदंग, ढोल नगाड़े के साथ विधिवत पूजा अर्चना की गई फिर बाजे -गाजे के साथ भगवान का बारात नगर भ्रमण के लिए रवाना हुआ। नगर निवासी अपने-अपने निवास स्थल एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठान के सामने सपरिवार हाथों में फूल माला, नारियल, अगरबत्ती एवं आरती के लिए पूजा की थाली लिए भगवान की प्रतीक्षा करते दिखाई दिए, जैसे ही झांकी उनके सामने से गुजरते गई लोगों ने बड़े ही श्रद्धा भक्ति पूर्वक पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया । इस दौरान जगह-जगह पर केला, सेव, जलेबी, मिठाई, लड्डू, ड्राई फ्रूट एवं पेय पदार्थ बारातियों को वितरित कर के ऊनका भव्य स्वागत किया वहीं अनेकों स्थानों पर बारातियों को साल,गमछा, माताओं को साड़ियां आदि वितरित करके पुण्य लाभ अर्जित किया।नगर वासियों ने जहां एक ओर जगह-जगह पर भगवान के बरतिया के स्वागत में जोरदार आतिशबाजियां की वहीं दूसरी ओर अपने-अपने दरवाजे पर दीप प्रज्वलित कर भगवान का स्वागत किया। देश के अनेक स्थानों से आए हुए संत महात्माओं एवं साध्वी माताओं की संख्या भी काफी अधिक थी , वे बाराती बनकर नाचते गाते चले जा रहे थे जो आकर्षण का केंद्र बना था। भगवान के बाराती बनने का उत्साह इतना ज्यादा था की बरतिया में न केवल नवयुवक नवयुतियां बल्कि छोटे-छोटे बच्चों से लेकर के 80-85 साल के बुजुर्ग भी भीड़ में धक्का मुक्की का बिना कोई परवाह किए प्रसन्न मन से चले जा रहे थे।

मठ में विधिवत विवाह संपन्न

बारात नगर भ्रमण करते हुए लगभग 8 :30 बजे शिवरीनारायण मठ पहुंचा नगर की माताओं ने द्वार परछन कर दूल्हा-दुल्हन को अंदर ले जाकर उनका विधिवत विवाह संस्कार पूर्ण कर आशीर्वाद प्राप्त किया। माताओं ने टिकावन की रस्म भी पूरी की। लोग भक्ति संगीत में झूमते दिखाई दिए। श्री सीताराम विवाह बारात महोत्सव में मुख्य रूप से महामंडलेश्वर राजेश्री महन्त रामसुन्दर दास जी महाराज, अनंत श्री विभूषित श्री स्वामी मधुसूदनाचार्य जी महाराज, स्वामी राम मनोहर दास जी महाराज छतरपुर (मध्य प्रदेश), स्वामी राम शिरोमणि दास जी महाराज प्रयागराज, त्यागी जी महाराज, मुखियार सुखराम दास जी, राघवेंद्र प्रताप सिंह, बृजेश केसरवानी, हेमंत दुबे, वीरेंद्र तिवारी, विश्वनाथ त्रिवेदी,पूर्णेन्द्र तिवारी, दिनेश दुबे,सुबोध शुक्ला, देवालाल सोनी,कमलेश सिंह, अशोक शर्मा, ज्ञानेश शर्मा, राजेश तंबोली बिलासपुर, त्रंबकेश्वर वैष्णव, संतोष वैष्णव, सीताराम नायक, रमेश वैष्णव ,शरद पांडे, भूपेंद्र पांडे, नटवर अग्रवाल, गोविंद यादव, शरद शर्मा, जगदीश यादव,राम अवतार दास जी, मीडिया प्रभारी निर्मल दास वैष्णव, हर्ष दुबे सहित अनेक गणमान्य नागरिक गण सम्मिलित हुए।

केशरी कॉलेज ऑफ फॉर्मेसी खोखरा, जांजगीर के प्रथम वर्ष का परीक्षा परिणाम शत प्रतिशत रहा

जांजगीर चांपा / छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद विश्व विद्यालय भिलाई द्वारा डी फॉर्मेसी प्रथम वर्ष का मुख्य परीक्षा परिणाम घोषित किया गया । जिसमें केशरी कॉलेज ऑफ फार्मेसी खोखरा,जांजगीर के डी. फार्मेसी प्रथम वर्ष के परीक्षा परिणाम में सभी छात्र - छात्राओं ने परीक्षा में

शानदार प्रदर्शन करते हुए उत्कृष्ट स्थान प्राप्त किया है। इस उपलब्धि से महाविद्यालय में खुशी की लहर दौड़ गई है । विद्यार्थियों की कड़ी मेहनत और महाविद्यालय के योग्य प्राध्यापकों के मार्गदर्शन को इसका श्रेय दिया जा रहा है। महाविद्यालय प्रशासन ने छात्रों को आगे की पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया है और भविष्य में भी इसी तरह की सफलता की कामना की है।

डी फॉर्मेसी प्रथम वर्ष के फार्मासिस्ट छात्र योगेंद्र कुमार ने 84 प्रतिशत अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान हासिल किया। नेहा पटेल 83 प्रतिशत अंक के साथ द्वितीय स्थान पर रही , राधारानी 82 प्रतिशत अंक के साथ तृतीय स्थान पर रही , यशकुमारी साहू 81 प्रतिशत, नेहा कश्यप 80 प्रतिशत, उमेश पटेल 80 प्रतिशत ,जगदीश कुमार 79 प्रतिशत, बिंदु कश्यप 78 प्रतिशत, विकाश पाण्डेय 78 प्रतिशत, नारायण 78 प्रतिशत अंकों के साथ उत्कृष्ट परिणाम से डी फार्मेसी प्रथम वर्ष की परीक्षा में कक्षा में अपना स्थान बनाया । इन सभी के साथ ही देवेंद्र कश्यप , , हेम सिंह, हेमलाल देवांगन,विनीता , दुर्गेश्वरी, तरुण देवांगन, सचिन , ईश्वर प्रसाद,

वैभव जयसवाल, अभिषेक कुमार , अनिल पटेल, जगबाई , दिनेश कुमार , मीना ,जैनेंद्र कुमार, विधाता नामदेव, दीनू बंजारे, गणपति दास महंत सभी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए।इस उपलब्धि पर संस्था के संचालक डॉ.सुरेश यादव के ने कहा कि महाविद्यालय के प्राचार्य एवं प्राध्यापकों द्वारा विद्यार्थियों के प्रोत्साहन फलस्वरूप अच्छा परीक्षा परिणाम प्राप्त हुआ है।

निधन ....श्रीमती जानकी देवी शर्मा

जांजगीर चांपा कुश कुमार शर्मा लेखपाल की माताजी श्रीमती जानकी देवी शर्मा का निधन 90 साल की उम्र में आज रात्रि 11:00 बजे हो गया है यह अशोक शर्मा पत्रकार की भाभी श्री थी एवं राजू शर्मा पत्रकार ऋषि शर्मा की बड़ी मां थी जिनका निधन हो गया है उनकी अंतिम यात्रा दिनांक 27 11. 25 को सुबह 10:00 बजे अंतिम यात्रा निवास कुबेरपारा से मारवाड़ी मुक्ति धाम के लिए रवाना होकर अंतिम संस्कार किया गया द्य अंतिम संस्कार पश्चात श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

निगम जोन 4 ने प्राप्त जनशिकायत को तत्काल संज्ञान में लेकर नेताजी सुभाष स्टेडियम से मालवीय रोड मुख्य बायपास मार्ग में खुली बड़ी नाली को तत्काल ढाक कर आवागमन हेतु किया सुरक्षित 0

रायपुर -

रायपुर नगर पालिक निगम को प्राप्त जनशिकायत को तत्काल संज्ञान में लेते हुए आयुक्त श्री विश्वदीप द्वारा दिए गए आदेशानुसार और नगर निगम जोन 4 जोन कमिश्नर श्री अरुण ध्रुव द्वारा दिए गए निर्देशानुसार नगर निगम जोन 4 क्षेत्र अंतर्गत नेताजी सुभाषचन्द्र बोस स्टेडियम से बैजनाथपारा होकर मालवीय रोड जाने वाले मुख्य बायपास मार्ग में मार्ग के किनारे खुली बड़ी नाली को तत्काल ढाक कर आवागमन के लिए आमजनों के लिए सुरक्षित करते हुए प्राप्त जनशिकायत का त्वरित निदान किया गया।

जिला रोजगार कार्यालय में 02 दिसम्बर को प्लेसमेंट कैंप का होगा आयोजन

जांजगीर-चांपा जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र जांजगीर-चांपा द्वारा युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से 02 दिसम्बर 2025 को प्रातः 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, जांजगीर-चांपा लाईवलीहुड कॉलेज परिसर जॉजगीर में प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि शिविर में निजी क्षेत्र के नियोजक गुडलक किसान ट्रैक्टर जांजगीर द्वारा सेल्स एक्जिक्टिव 10, फाईनेंस मैनेजर 04 एवं कंप्यूटर ऑपरेटर 02, पदों पर एवं बाम्बे इंटीग्रेटेड सिक्युरिटी सर्विस, रायपुर द्वारा सिक्युरिटी गार्ड के 100 पदों पर भर्ती की कार्यवाही की जावेगी। पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता कक्षा 10वीं से स्नातक तक निर्धारित की गई है। चयनित उम्मीदवारों का कार्यक्षेत्र जांजगीर चांपा, रायपुर एवं सिलतरा रहेगा। उक्त पदों के लिए वेतनमान 8000 से 18000 रुपए निर्धारित की गई है एवं महिला एवं पुरुष दोनों पात्र होगें। प्लेसमेंट कैंप में भाग लेने वाले इच्छुक आवेदक अपने मूल प्रमाण पत्रों के साथ स्वयं उपस्थित होकर कैंप में भाग ले सकते है। अधिक जानकारी के लिए जिला रोजगार कार्यालय जांजगीर-चांपा से भी संपर्क किया जा सकता है।

नगर निगम रायपुर द्वारा नगर के आमजनों से सफाई कार्य संबंधित प्राप्त शिकायत का त्वरित निराकरण किया

रायपुर - रायपुर नगर पालिक निगम की स्वास्थ्य अधिकारी डॉ तृप्ति पाणीग्रही ने जानकारी दी है कि नगर पालिक निगम रायपुर के मुख्यालय के अंतर्गत कुल 230 सफाई कर्मचारी कार्यरत है, जिसकी लगातार मॉनिटरिंग की जाती है तथा उनका ग्रुप में विभाजन कर सेन्ट्रल गैंग व महापौर स्वच्छता सेल के तहत सभी जोनों में सफाई कार्य हेतु लगाया जाता है। प्रतिदिन वी.वाई.पी. कार्यक्रमों, आकस्मिक पर्व आंयोजनों, वी.आई.पी. बंगलों के बाहरी परिसर की सफाई, प्रतिदिन प्रमुख मार्गों, वी.आई.पी. रोड, एक्सप्रेस-वे, कैनाल रोड की सफाई, महादेवघाट, तालाबों, बड़े नालों तथा व्यवसायिक क्षेत्रों की सफाई आदि स्थलों को नियमित एवं विशेष अवसरों पर सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है। प्रतिदिन जनप्रतिनिधियों एवं जोन स्वास्थ्य अधिकारियों के मांगध्आवश्यकतानुसार विभिन्न धाडों में सफाई कार्य संपन्न किया जाता है। इन कर्मचारियों।

संविधान दिवस पर विद्या निकेतन व ड्रिमलैंड स्कूल के द्वारा निकाली गई रैली

जांजगीर चांपा / राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई विद्या निकेतन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पामगढ़ एवं ड्रीमलैंड पब्लिक स्कूल पामगढ़ के संयुक्त तत्वाधान से 26 नवंबर 2025 को ÷संविधान दिवस÷ के अवसर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को याद करते हुए एवं समाज में भारतीय संविधान के महत्व को बतलाने के उद्देश्य से विद्यालय के बच्चों द्वारा विद्यालय परिसर से तहसील चौक होते हुए अंबेडकर चौक तक भव्य रैली का आयोजन किया गया था।

साथ ही समस्त शिक्षक एवं शिक्षिकाओं तथा विद्यार्थियों द्वारा भारतीय संविधान के उद्देशिका को पढ़कर शपथ लिया गया, एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के बच्चों एवं विद्यालय परिवार के बच्चों के लिए एक संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया था ,जिसमें आज के दिन के महत्व को बच्चों को बताया तथा 26 / 11 मुंबई हमले के शहीदों की आत्मा की शांति हेतु ईश्वर से प्रार्थना किया गया और उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित किया गया।

इस भव्य रैली का संचालन विद्यालय संचालक आदरणीय नरेंद्र कुमार पांडे जी , अशोक कुमार मिरे,(प्राचार्य विद्या निकेतन) दीपक प्रधान (प्राचार्य ड्रीमलैंड स्कूल) अखिल शुक्ला (विभाग प्रमुख) अर्जुन लाल यादव (उपप्राचार्य) वीरेंद्र कुमार खुटे (रासेयो कार्यक्रम अधिकारी)

नेहा खरे, सुरेश साहू, अंकित तिवारी, संजना साहू, (रासेयो सहकार्यक्रम अधिकारी) एवं समस्त विद्यालय शिक्षक/ शिक्षिकाओं की उपस्थिति में कार्यक्रम को सफल बनाया गया।

सिद्धिविनायक राइस मिल का हुआ शुभारंभ

जांजगीर चांपा / गिधौरी के समीप ग्राम हसुवा स्थित सिद्धि विनायक राइस मिल का शुभारंभ महामंडलेश्वर राजेश्री महन्त रामसुन्दर दास जी महाराज एवं संत गोपाल दास जी महाराज की गरिमामय उपस्थिति में संपन्न हुआ । इन्होंने फीता काटकर, स्विच ऑन करके राइस मिल का शुभारंभ किया एवं इसके संचालक बंसल परिवार को शुभकामनाओं सहित भगवान शिवरीनारायण का तैल चित्र भेंट करके आशीर्वाद प्रदान किया। बंसल परिवार के द्वारा अतिथियों का सम्मान शाल,पुष्प माला, श्रीफल भेंट करके किया गया। इस अवसर पर विशेष रूप से शिवरीनारायण मठ के मुख्तियार सुखराम दास जी, विश्व दयाल बंसल, दीपक बंसल, निलेश बंसल, अमित बंसल, जगदीश अग्रवाल, योगेश अग्रवाल, मीडिया प्रभारी निर्मल दास वैष्णव, हर्ष दुबे, सुरेश साहू सहित अनेक गणमान्य नागरिक गण उपस्थित थे।

शासन की संवेदनशील धान खरीदी नीति से किसानों को मिल रही राहत - किसान श्री संतोष कुमार

घर बैठे टोकन, पारदर्शी तौल, धान खरीदी व्यवस्था से श्री संतोष कुमार का बढ़ा आत्मविश्वास

जांजगीर-चांपा, जांजगीर-चांपा जिले के खरौद में रहने वाले किसान श्री संतोष कुमार की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आया है। कुछ वर्षों पहले तक धान बेचने की प्रक्रिया उनके लिए मुश्किलों से भरी रही। धूप में भूने हुए दिन, रातभर की बेचैनी, भीड़भाड़ में लंबी कतारें, तौल और भुगतान को लेकर असमंजस - ये सब उनकी खेती-किसानी का हिस्सा बन चुके थे। लेकिन शासन की पारदर्शी और तकनीक आधारित धान खरीदी व्यवस्था ने उनकी दुनिया ही बदल दी।

किसान श्री संतोष कुमार जब खरौद धान उपार्जन केंद्र पहुंचे, तो उन्होंने पहली बार महसूस किया कि सरकारी व्यवस्थाएँ भी

किसान के हित में कितनी प्रभावी हो सकती हैं। केंद्र में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या अवांछित भीड़ नहीं थी। साफ-सुथरा माहौल, सहयोगी कर्मचारियों की उपस्थिति, निर्धारित समय पर टोकन की उपलब्धता और तौल प्रक्रिया की पारदर्शिता ने उन्हें पहली ही नजर में प्रभावित कर दिया। उन्होंने बताया कि यह बदलाव सिर्फ व्यवस्थाओं में नहीं, बल्कि किसानों के मनोबल में भी आया है। श्री संतोष कुमार ने 53 क्विंटल धान बेचा। पहले जहां उन्हें धान बेचने में कई दिन लग जाते थे, वहीं अब कुछ ही घंटों में संपूर्ण प्रक्रिया पूरी हो गई। न कोई भागदौड़, न कोई अनिश्चितता और न ही बेवजह की परेशानी। वे बताते हैं कि तौल प्रक्रिया में पारदर्शिता से उन्हें एक अलग ही विश्वास मिला है।

किसान श्री संतोष कुमार अपने अनुभव बताते हुए कहते हैं कि पहले धान खरीदी के दिनों में घर की चिंताओं और आर्थिक अनिश्चितता का बड़ा दबाव रहता था। लोकिन इस बार स्थिति पूरी तरह बदली है। धान बेचकर घर लौटते समय उनके चेहरे पर एक अलग चमक थी, मानो वर्षों पुराना बोझ उतर गया हो। उन्होंने कहा कि अब वे निश्चिंत होकर परिवार के साथ समय बिता पा रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई, घर की जरूरतें, खेती की योजनाएँ सब कुछ व्यवस्थित तरीके से सोच पा रहे हैं, क्योंकि आय सुनिश्चित है, भुगतान समय पर मिल रहा है और प्रक्रिया में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं रही। सरकार द्वारा शुरू किया गया 'टोकन तुहर हाथ' मोबाइल एप उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं। पहले टोकन के लिए केंद्र तक जाना पड़ता था, भीड़ का सामना करना पड़ता था और कई बार पूरा दिन बर्बाद हो जाता था। लेकिन अब घर बैठे टोकन बुक करने से न सिर्फसमय की बचत हो रही है, बल्कि व्यवस्था में एक नई पारदर्शिता और सम्मान का भाव भी मिल रहा है।

खास खबर

गोलबाजार में ट्रैफिक अभियान के दौरान एएसपी और व्यापारियों में तीखी बहस, वीडियो वायरल

बिलासपुर, न्यायधानी के गोलबाजार क्षेत्र में सोमवार को अतिक्रमण हटाने पहुंची ट्रैफिक पुलिस की टीम और स्थानीय व्यापारियों के बीच जमकर विवाद हो गया। कार्रवाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एडिशनल एसपी ट्रैफिक रामगोपाल करियारे और व्यापारियों के बीच तीखी नोकझोंक देखी जा सकती है।

सूत्रों के अनुसार, एएसपी करियारे अपनी टीम के साथ गोलबाजार और सदर बाजार में यातायात सुधार अभियान चला रहे थे। इस दौरान सड़क किनारे गलत ढंग से पार्क की गई गाड़ियों को जब्त करने की कार्रवाई शुरू की गई। इसी बात पर एक व्यापारी ने आपत्ति जताई और एएसपी से बहस करते हुए तंज भरे लहज़े में कहा– सर, आपकी पढ़ाई को दाद देता हूं। इस टिप्पणी के बाद स्थिति गरमा गई। विवाद की जड़ सफेद पट्टी वाली पार्किंग को लेकर थी। व्यापारियों का कहना था कि वे तयशुदा निशान के भीतर ही वाहन खड़े कर रहे थे, जबकि पुलिस का तर्क था कि बाजार में सुचारू यातायात व्यवस्था के लिए सड़क खाली रखना आवश्यक है।

एएसपी करियारे ने मौके पर स्पष्ट कहा कि शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं और सड़क सार्वजनिक संपत्ति है, जिस पर अवैध कब्जा या मनमानी पार्किंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

कटघोरा में बढ़ती सड़क दुर्घटनाएँ : पुलिस ने नगर पालिका सीएमओ को थमाया नोटिस

कोरबा । शहर में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए कटघोरा पुलिस ने नगर पालिका के मुख्य नगरपालिका अधिकारी (सीएमओ) मुद्रिका प्रसाद तिवारी को नोटिस जारी किया है। पुलिस का कहना है कि नगर के मुख्य मार्गों पर बने डिवाइडरों के बीच उचित सांकेतक बोर्ड न होने से दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है।

जारी नोटिस में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि यदि जल्द ही डिवाइडरों पर संकेतक बोर्ड नहीं लगाए गए और भविष्य में कोई सड़क हादसा होता है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी नगर पालिका प्रशासन विशेषकर सीएमओ की होगी। पुलिस ने बताया कि रात के समय कई स्थानों पर डिवाइडर दिखाई नहीं देते, जिसके कारण वाहन चालकों का संतुलन बिगड़ता है और हादसे की आशंका बढ़ जाती है। नगरवासियों की शिकायतों और हाल ही में बढ़े दुर्घटनाओं के मामलों को ध्यान में रखते हुए यह कार्रवाई की गई है। स्थानीय लोगों ने भी नगर पालिका से सड़क सुरक्षा के प्रति लापरवाही समाप्त करने और जल्द कार्रवाई करने की मांग की है, ताकि शहर में सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित हो सके।

निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य को त्रुटिरहित रूप से निर्धारित समयावधि में पूरा कराएं - आयुक्त

0 आयुक्त आशुतोष पाण्डेय ने निगम के जोन कमिश्नरों की बैठक लेकर एस.आई.आर. की कार्यप्रगति की विस्तार से समीक्षा की

कोरबा आयुक्त आशुतोष पाण्डेय ने नगर पालिक निगम कोरबा के जोन कमिश्नरों व प्रभारी अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि निर्वाचक नामावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य को त्रुटिरहित स्वरूप में संपादित कराते हुए निर्धारित समयसीमा में कार्य को पूरा कराएं, अपने अधिनस्थ स्टाफ को इस कार्य बी.एल.ओ., सुपरवाईजर को सभी आवश्यक सहयोग देने हेतु निर्देशित करें, साथ ही प्रतिदिन की कार्यप्रगति की जानकारी अपडेट करते हुए आमनागरिकों, मतदाताओं को सतत रूप से प्रेरित व प्रोत्साहित करें कि वे एस.आई.आर. की सही जानकारी फार्म में भरकर अपने बी.एल.ओ. के पास जमा कराएं।

यहाँ उल्लेखनीय है कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के तहत कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अजीत वसंत के मार्गदर्शन में कोरबा जिले में निर्वाचक नामावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य प्रगति पर है तथा जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में बी.एल.ओ. द्वारा घर -घर जाकर मतदाताओं से गणना पत्रक भरवाने व बी.एल.ओ. एप के माध्यम से डिजिटल प्रवृष्टि करने का कार्य प्रगति पर है। कोरबा शहरी क्षेत्र व नगर पालिक निगम कोरबा क्षेत्रांतर्गत सभी वार्डो में भी विशेष गहन पुनरीक्षत का यह कार्य जारी है। आज निगम आयुक्त श्री आशुतोष पाण्डेय ने निगम के सभी जोन कमिश्नरों व प्रभारी अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक लेकर निगम क्षेत्र में निर्वाचक नामावलियों के किए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य की कार्यप्रगति की विस्तार से समीक्षा की तथा उक्ताशय के निर्देश जोन कमिश्नरों को दिए। बैठक के दौरान एस.डी.एम. सरोज महिलांगे, अपर आयुक्त विनय मिश्रा, उपायुक्त पवन वर्मा, नीरज कौशिक, बी.पी.त्रिवेदी, जोन कमिश्नर विनोद शांडिल्य, भूषण उरांव, अखिलेश शुक्ला, प्रकाश चन्द्रा, तपन तिवारी, एन.के.नाथ, सुनील टांडे, राकेश मसीह आदि के साथ अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

वर्ष 2003 की नामावली में नाम न होने पर इन 11 में से कोई भी एक दस्तावेज आवश्यक- आयुक्त श्री आशुतोष पाण्डेय ने बैठक में कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार गणना पत्रक भरने एवं डिजिटाईजेशन की अवधि 04 नवम्बर 2025 से 04 दिसम्बर 2025 तक है। उन्होने कहा कि वर्ष 2003 की निर्वाचक नामावली में संबंधित मतदाता का स्वयं या उनके माता-पिता का नाम होने पर किसी प्रकार की दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी किन्तु यदि 2003 की निर्वाचक नामावली में स्वयं या माता-पिता का नाम नहीं होगा तो इन 11 प्रकार के दस्तावेजों में से किसी एक दस्तावेज का होना अनिवार्य है। इन दस्तावेजों में ? नियमित कर्मचारी पेंशनभोगी को केन्द्र/राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रम द्वारा जारी पहचान पत्र या पेंशन भुगतान आदेश, ? 01 जुलाई 1987 से पूर्व भारत में किसी भी सरकारी, स्थानीय निकाय, बैंक, डाकघर, एलआईसी, पीएसयू द्वारा जारी पहचान पत्र या प्रमाण पत्र के दस्तावेज, ? सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र, ? पासपोर्ट ? मैट्रिकुलेशन या शैक्षणिक प्रमाणपत्र (मान्यता प्राप्त बोर्ड, विश्वविद्यालय द्वारा जारी) ? स्थायी निवास प्रमाणपत्र (सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी) ? वन अधिकार प्रमाणपत्र ? ओ.बी.सी., एस.सी. एस.टी या अन्य जाति प्रमाणपत्र (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी) ??राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर - जहाँ लागू हो ? परिवार रजिस्टर (राज्य , स्थानीय प्राधिकरण द्वारा तैयार)?? सरकार द्वारा जारी भूमि, मकान आवंटन प्रमाणपत्र आदि शामिल है। एसआईआर फार्म भरने हेतु नवीन फोटो की आवश्यकता नहीं है, जो पूर्व में है उससे अपडेट किया जाएगा यदि कोई नवीन फोटो देता है तो स्वीकार्य किया जाएगा।

मिशन वरूण को मिल रही आशातीत सफलता, जलकर जमा करने आगे आ रहे लोग, जल संरक्षण के लिए हो रहे प्रेरित

o सोमवार को एक ही दिन में जमा हुआ 01 लाख रू.से अधिक बकाया जलकर, अब तक 06 लाख 85 हजार रू. की जलकर राशि जमा कराई लोगों ने

कोरबा (आरएनएस)। बर्षो से बकाया जलकर की वसूली एवं जल संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता लाने हेतु नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा संचालित किए जा रहे '' मिशन वरूण '' को आशातीत सफलता मिल रही है, एक ओर जहॉ लोग बर्षो से बकाया जलकर की राशि निगम में जमा करा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जल संरक्षण एवं पानी के व्यर्थ बरबादी के प्रति जागरूक होकर जल के अपव्यय को रोक रहे हैं। सोमवार को एक ही दिन में 01 लाख रूपये से अधिक की बकाया जलकर राशि लोगों द्वारा जमा कराई गई, वहीं पिछले 10 दिनों में अब तक 06 लाख 85 हजार रूपये बकाया जलकर की राशि निगम कोष में जमा कराई जा चुकी है।

यहॉ उल्लेखनीय है कि नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा अपने क्षेत्रांतर्गत सभी वार्ड व बस्तियों, शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल की पर्याप्त आपूर्ति जलप्रदाय की विशाल संरचनात्मक ढांचे के माध्यम से प्रतिदिन दो बार की जा रही है तथा इस हेतु नियमानुसार जलकर की राशि आरोपित की गई है किन्तु बर्षो से जलकर की वसूली नहीं हो पा रही थी, जिसके मद्देनजर निगम द्वारा महापौर श्रीमती संजूदेवी राजपूत एवं आयुक्त श्री आशुतोष पाण्डेय के मार्गदर्शन में एक अभिनव कदम उठाते हुए '' मिशन वरूण '' की शुरूआत विगत 14 नवम्बर 2025 को की गई, '' मिशन वरूण '' का प्रमुख उद्देश्य एक ओर जहॉ बर्षो से बकाया जलकर की राशि निगम कोष में जमा कराने का है, वहीं दूसरी ओर जल संरक्षण व पानी की व्यर्थ बरबादी के प्रति लोगों के बीच जनजागरूकता लाकर जल के अपव्यय को रोकना भी है। निगम द्वारा विगत 10 दिवस से संचालित किए जा रहे '' मिशन वरूण '' को आशातीत सफलता मिल रही है, जलकर के बकायादार व आमनागरिक जलकर की राशि को जमा कराने हेतु आगे आ रहे हैं, '' मिशन वरूण '' की टीम को अपना सहयोग दे रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर जल संरक्षण के प्रति जागरूक भी हो रहे है, पानी के अपव्यय को रोक रहे हैं। निगम के कार्यपालन अभियंता जलप्रदाय श्री राकेश मसीह ने बताया कि विगत 10 दिनों में निगम कोष में 06 लाख 85 हजार रूपये की बकाया जलकर राशि जमा कराई जा चुकी है, जबकि सोमवार को केवल 01 ही दिन में 01 लाख रूपये से अधिक की जलकर राशि लोगों द्वारा जमा कराई गई है।

घर-घर पहुंच रही टीमें, लोगों को कर रही प्रेरित व प्रोत्साहित - '' मिशन वरूण '' टीम के सदस्य वार्ड एवं बस्तियों में पहुंचकर घर-घर दस्तक दे रहे हैं तथा आम लोगों को जल का संरक्षण करने, पानी का अपव्यय रोकने व निगम को देय जलकर का समय पर भुगतान करने आदि के लिए प्रेरित व प्रोत्साहित कर रहे हैं।

पोड़ी में 30 बोरी अवैध धान किया गया जप्त

कोरबा कलेक्टर श्री अजीत वसंत के निर्देशन में जिला प्रशासन द्वारा जिले में अवैध धान के परिवहन, भंडारण व विक्रय पर नियंत्रण लगाने गम्भीरता से कार्यवाही किया जा रहा है। इसी कड़ी में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पाली श्री रोहित सिंह के मार्गदर्शन मे तहसीलदार पाली भूषण सिंह एवं नायब तहसीलदार पाली सुजीत पाटल, हल्का पटवारी एवं कोटवार के द्वारा ग्राम पोड़ी में कोचिए के घर में अवैध रूप से भंडारित लगभग 30 बोरी धान को जप्त किया गया है एवं आगे कार्यवाही की जा रही है।

रेत के अवैध परिवहन में लगे 2 ट्रैक्टर किया गया जब्त

बांधाखार में शासकीय भूमि पर अवैध रूप से मिट्टी पटाई कार्य में लगे जेसीबी व टीपर वाहन को किया गया जब्त

कोरबा । जिला प्रशासन द्वारा रेत के अवैध खनन एवं परिवहन पर नियंत्रण एवं शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा पर रोक लगाने हेतु गम्भीरता से कार्यवाही किया जा रहा है। इसी कड़ी में कलेक्टर श्री अजीत वसंत के मार्गदर्शन में एसडीएम पाली श्री रोहित सिंह के दिशा निर्देश पर नायब तहसीलदार पाली श्री सुजीत कुमार पाटले एवं राजस्व निरीक्षक पोड़ी व हल्का पटवारी के द्वारा ग्राम पोड़ी में अवैध रूप से रेत खनन कर परिवहन करते हुए 2 ट्रैक्टर को जप्त कर थाना पाली को सुपुर्द किया गया है।

इसी प्रकार अनुविभाग पाली के हरदीबाजार तहसील अंतर्गत ग्राम बांधाखार में बिना अनुमति अवैध रूप से शासकीय भूमि पर मिट्टी पटाई कार्य में लगे जेसीबी एवं टीपर वाहन को राजस्व टीम द्वारा जब्त कर हरदीबाजार थाना में सुपुर्द किया गया है। एसडीएम पाली ने कहा कि अनुविभाग में शासकीय भूमि पर किसी भी तरह की अवैध कब्जा एवं रेत सहित अन्य खनिजों के अवैध खनन व परिवहन पर गम्भीरता से कार्यवाही की जाएगी। आगे भी इस प्रकार की कार्यवाही जारी रहेगी।

गोलबाजार में ट्रैफिक अभियान के दौरान एएसपी और व्यापारियों में तीखी बहस, वीडियो वायरल

बिलासपुर, न्यायधानी के गोलबाजार क्षेत्र में सोमवार को अतिक्रमण हटाने पहुंची ट्रैफिक पुलिस की टीम और स्थानीय व्यापारियों के बीच जमकर विवाद हो गया। कार्रवाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एडिशनल एसपी ट्रैफिक रामगोपाल करियारे और व्यापारियों के बीच तीखी नोकझोंक देखी जा सकती है।

सूत्रों के अनुसार, एएसपी करियारे अपनी टीम के साथ गोलबाजार और सदर बाजार में यातायात सुधार अभियान चला रहे थे। इस दौरान सड़क किनारे गलत ढंग से पार्क की गई गाड़ियों को जब्त करने की कार्रवाई शुरू की गई। इसी बात पर एक व्यापारी ने आपत्ति जताई और एएसपी से बहस करते हुए तंज भरे लहज़े में कहा– सर, आपकी पढ़ाई को दाद देता हूं। इस टिप्पणी के बाद स्थिति गरमा गई। विवाद की जड़ सफेद पट्टी वाली पार्किंग को लेकर थी। व्यापारियों का कहना था कि वे तयशुदा निशान के भीतर ही वाहन खड़े कर रहे थे, जबकि पुलिस का तर्क था कि बाजार में सुचारू यातायात व्यवस्था के लिए सड़क खाली रखना आवश्यक है। एएसपी करियारे ने मौके पर स्पष्ट कहा कि शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं और सड़क सार्वजनिक संपत्ति है, जिस पर अवैध कब्जा या मनमानी पार्किंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

जागो ग्राहक जागो, अपन हक ल पहचानो : जिला उपभोक्ता आयोग कोरबा द्वारा उपभोक्ता जागरूकता शिविर

कोरबा जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग कोरबा द्वारा प्रतिमाह जिले के विभिन्न ग्राम पंचायतों में उपभोक्ता जागरूकता शिविर आयोजित कर ग्रामीणों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज करतला विकासखण्ड की ग्राम पंचायत ढोढातराई में उपभोक्ता जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।कार्यक्रम में जिला उपभोक्ता आयोग की अध्यक्षा श्रीमती रंजना दत्ता एवं सदस्यगण सुश्री ममता दास व श्री पंकज कुमार देवड़ा की गरिमामय उपस्थिति रही।

उपभोक्ता जागरूकता शिविर में महिलाओं, छात्र-छात्राओं, वरिष्ठ नागरिकों, ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों, मितानिन समूह एवं आम उपभोक्ताओं को उनके उपभोक्ता अधिकारों और कानूनी संरक्षण के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। आयोग की अध्यक्षा श्रीमती रंजना दत्ता एवं सदस्यगण ने बताया कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत प्रत्येक उपभोक्ता को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण वस्तु और सेवा प्राप्त करने, उचित मूल्य चुकाने, जानकारी प्राप्त करने, शिकायत दर्ज करने और क्षतिपूर्ति पाने का वैधानिक अधिकार है।

ग्रामीणों को उपभोक्ता कानून के संबंध में बताया गया कि यदि किसी वस्तु या सेवा में कमी, अनुचित व्यापार व्यवहार, ओवर बिलिंग, भ्रामक विज्ञापन या सेवा प्रदाय में लापरवाही हो तो उपभोक्ता जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष सरल प्रक्रिया द्वारा वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। किराना, दवा, इलेक्ट्रॉनिक सामान, बीमा, बैंकिंग, स्वास्थ्य सेवा और ऑनलाइन शॉपिंग में उपभोक्ताओं को अपने हितों की सुरक्षा के लिए सचेत रहने की सलाह दी गई। डिजिटल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध सुविधाओं, ई-हियरिंग, ई-फाइलिंग, ऑनलाइन फ्रॉड, फिशिंग, फर्जी वेबसाइट व डिजिटल पेमेंट से जुड़े जोखिमों से बचाव हेतु व्यावहारिक सुझाव दिए गए।

कार्यक्रम में विशेष आमंत्रित वक्ता जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष श्री गणेश कुलदीप ने ग्रामीणों को उनके कानूनी अधिकारों और उपभोक्ता संरक्षण के महत्व से अवगत कराया तथा सभी से खरीदी गई वस्तुओं का बिल लेने की अपील की। जनपद सदस्य श्रीमती देवी बाई राजवाड़े ने भी उपभोक्ता आयोग द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी।

बालविवाह मुक्त जिला बनाने के लिए समन्वित प्रयास जरूरी– सीईओ

बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ हेतु एक दिवसीय कार्यशाला सम्पन्न

कोरबा । बाल विवाह करना एवं कराना कानूनन दंडनीय अपराध है। बाल विवाह संपन्न कराने वाले व्यक्तियों, जैसे पंडित, मौलवी आदि को न्यूनतम 2 वर्ष के कठोर कारावास का प्रावधान है। बाल विवाह की रोकथाम हेतु व्यापक स्तर पर जन-जागरूकता अभियान और प्रचार-प्रसार अनिवार्य है। यह बातें जिला पंचायत कोरबा में सोमवार को आयोजित एकदिवसीय कार्यशाला में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री दिनेश कुमार नाग ने कहीं।

श्री नाग ने कहा कि विशेष पिछड़ी जनजाति समुदायों में बाल विवाह की रोकथाम के लिए अतिरिक्त प्रयास करना आवश्यक है। महिला एवं बाल विकास विभाग, पुलिस, पंचायत एवं ग्रामीण विभाग, स्वयंसेवी संस्थाएँ आदि सभी के समन्वित प्रयासों से जिला ही नहीं, पूरा राज्य बाल विवाह मुक्त बनाया जा सकता है।

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार से प्राप्त निर्देशों के अनुक्रम में कलेक्टर सह-अध्यक्ष, जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति श्री अजीत वसंत के निर्देशानुसार तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री दिनेश नाग, जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री बसंत मिंज के मार्गदर्शन में जिले के सभी विद्यालयों एवं शैक्षणिक संस्थानों में जन-जागरूकता अभियान निरंतर संचालित किया जा रहा है।

इसी क्रम में महिला एवं बाल विकास विभाग एवं एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन के संयुक्त तत्वावधान में सोमवार को बाल विवाह प्रतिषेध विषय पर एकदिवसीय कार्यशाला सम्पन्न हुई। कार्यशाला में राज्य स्तरीय प्रशिक्षक श्री विपिन ठाकुर द्वारा विस्तृत प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इस अवसर पर सीईओ जिला पंचायत श्री दिनेश कुमार नाग ने उपस्थित बच्चों, अधिकारी,कर्मचारी, स्वयं सेवी संस्थाओं, विभिन्न सामाजिक समुदायों के जन प्रतिनिधियों को बाल विवाह न करने एवं न होने देने की शपथ दिलाई।

जिला बाल संरक्षण इकाई, महिला एवं बाल विकास विभाग एवं आभा के सहयोग से आयोजित इस कार्यशाला में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की प्रमुख धाराओं एवं प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी गई। बच्चों एवं प्रतिभागियों को कानूनी प्रावधानों के साथ सामाजिक जिम्मेदारी निभाने की भी शपथ दिलाई गई।

कार्यशाला में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, किशोर न्याय बोर्ड, परियोजना अधिकारी, सेक्टर पर्यवेक्षक, ग्राम पंचायत सचिव, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग, श्रम विभाग, बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य, एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन के प्रतिनिधि श्री विजय प्रताप, जिला बाल संरक्षण अधिकारी श्री दया दास महंत, धर्मगुरु, सेवा प्रदाता, चाइल्डलाइन 1098 टीम सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

राज्य से प्राप्त निर्देशों के अनुसार, पिछले दो वर्षों में जिन ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों में बाल विवाह का कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है, उन्हें बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत एवं बाल विवाह मुक्त नगरीय निकाय घोषित करने की प्रक्रिया प्रगति पर है।

धान तिहार 2025-26 सुचारू रूप से जारी, किसान हितैषी नीतियों से उपार्जन केंद्रों में उमड़ रहा उत्साह'

तुंहर टोकन से मिला सुगम अनुभव, पहले दिन श्री कैवर्त ने उत्साहपूर्वक विक्रय किया 40 क्विंटल धान'

विष्णु सरकार की प्राथमिकता : किसान और उनकी सुविधा

कोरबा)। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के अंतर्गत प्रदेशभर में धान खरीदी का उत्सव पूर्ण पारदर्शिता, सुव्यवस्था और उत्साह के साथ जारी है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में इस वर्ष समर्थन मूल्य 3100 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किए जाने तथा खरीदी केंद्रों में उपलब्ध सुविधाओं के व्यापक सुदृढ़ीकरण ने किसानों में अभूतपूर्व उत्साह पैदा किया है। राज्य सरकार द्वारा किसान हितैषी भावना के साथ किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप प्रदेश के सभी उपार्जन केंद्रों में खरीदी कार्य बिना किसी बाधा के सुचारू रूप से संपन्न हो रहा है। इसी सकारात्मक परिवेश के बीच जिले के ग्राम छुरी कला के किसान श्री विश्वनाथ कैवर्त ने भी इस वर्ष अपनी मेहनत की फसल को छुरी सहकारी समिति में विक्रय के लिए प्रस्तुत किया। करीब 02 एकड़ भूमि में खेती करने वाले श्री कैवर्त पूरी तरह कृषि पर निर्भर हैं। पिछले वर्ष उन्होंने लगभग 40 क्विंटल धान का विक्रय किया था, वहीं इस वर्ष भी वह 40 क्विंटल धान लेकर खरीदी केंद्र पहुँचे। श्री कैवर्त ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा धान खरीदी प्रक्रिया पहले की तुलना में और अधिक सरल और सुविधाजनक हुई है। उन्होंने कहा कि ÷ मैंने तुंहर टोकन ऐप से घर बैठे ही टोकन प्राप्त किया, जिससे समय की बचत हुई। छुरी सहकारी समिति में किसानों के लिए बेहद अच्छी व्यवस्था की गई है। बैठने की जगह, पेयजल, शौचालय, माइक्रो एटीएम और तुलाई की सुचारू व्यवस्था के कारण किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हुई।

संविधान दिवस पर टाउन हॉल में गरिमामय कार्यक्रम

रायपुर। संविधान दिवस के अवसर पर आज टाउन हॉल, शास्त्री चौक में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। उन्होंने डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा एवं उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री श्री साय की उपस्थिति में संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन किया गया, जिसमें सभी अतिथियों, अधिकारियों एवं विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने संविधान की महत्ता, उसके मूल्यों और नागरिक कर्तव्यों पर प्रेरक उद्बोधन दिया। उन्होंने कहा कि संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं, बल्कि भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों का आधार स्तंभ है। श्री साय ने कहा कि, आज सौभाग्य का विषय है कि हम सब 75 वां संविधान दिवस मनाने एकत्र हुए हैं। आप सभी लोगों को संविधान दिवस की बहुत बधाई व शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री श्री साय ने भारत माता और छत्तीसगढ़ महतारी के जयघोष के साथ बाबासाहब भीमराव अंबेडकर को नमन करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने संविधान दिवस पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया।

जनता की समस्याओं का समय पर प्रभावी समाधान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता : मंत्री अग्रवाल

रायपुर । पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने सरगुजा जिले के उदयपुर तहसील अंतर्गत ग्राम घाटबर्रा में ग्रामीणों से आत्मीयता के साथ संवाद कर उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना। ग्रामीणों की ओर से उठाए गए त्वरित समाधान योग्य मामलों का स्थल पर ही निराकरण किया, जबकि दीर्घकालिक विषयों के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा में समस्या के निराकरण के निर्देश दिए गए। मंत्री श्री अग्रवाल ने उपस्थित ग्रामीणों को आश्वस्त करते हुए कहा, जनता की समस्याओं का समय पर और प्रभावी समाधान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। ग्रामीण क्षेत्रों का समग्र विकास, बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता और जनकल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन हमारा मुख्य उद्देश्य है। सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता के साथ जनसेवा को प्राथमिकता दें। ग्रामीणों ने अपनी सभी समस्याओं से पर्यटन मंत्री श्री अग्रवाल को अवगत कराया। मंत्री ने उनकी हर बात को गंभीरतापूर्वक सुना और मौके पर ही समाधान योग्य समस्याओं का निराकरण किया, उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से लेकर समय-सीमा में उसका निराकरण सुनिश्चित करें। श्री अग्रवाल के सहज, सरल और सुलभ व्यवहार से प्रभावित ग्रामीणों ने उनकी संवेदनशीलता, त्वरित निर्णय क्षमता और विकास के प्रति प्रतिबद्धता की सराहना की।

वन मंत्री श्री केदार कश्यप ने अधिकारियों की बैठक ली अधिकारियों की बैठक ली

रायपुर। वन एवं जलवायु परिवर्तन तथा सहकारिता मंत्री श्री केदार कश्यप ने आज कोंडागांव जिला कार्यालय के सभाकक्ष में अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र में चल रही शासकीय योजनाओं और निर्माण कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई।

बुनियादी सुविधाओं के सुदृढ़ विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए

मंत्री श्री कश्यप ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सुदूर अंचलों में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं के सुदृढ़ विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि सभी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक समय पर पहुंचे। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रीता शोरी, कलेक्टर श्रीमती नुपूर राशि पन्ना, पुलिस अधीक्षक श्री पंकज चंद्रा और डीएफओ श्री चूड़ामणि सिंह उपस्थित रहे।

स्वास्थ्य केंद्रों में कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करें

बैठक में मंत्री श्री कश्यप ने दूरस्थ स्वास्थ्य केंद्रों में आवश्यक संसाधन और कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने गर्भवती माताओं और कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण पर गंभीरता से काम करने पर जोर दिया। इसके साथ ही विभिन्न विभागों के निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि सभी कार्य गुणवत्तापूर्ण हों और निर्धारित समय सीमा में पूरे किए जाएं।

श्रम पंजीयन में तेजी लाने निर्देश

मंत्री श्री कश्यप ने सभी ग्राम पंचायतों को विकासखण्ड मुख्यालय से बेहतर सड़क और अन्य सुविधाओं के माध्यम से जोड़ने के लिए योजनाबद्ध रूप से कार्य करने को कहा, ताकि प्रत्येक गांव तक आवश्यक सेवाएं आसानी से पहुंच सकें। उन्होंने श्रम पंजीयन में तेजी लाने के लिए गांव-गांव में शिविर आयोजित करने और ग्रामीणों को पशुपालन, दुग्ध उत्पादन और मत्स्यपालन जैसी गतिविधियों से जोड़कर आर्थिक रूप से मजबूत बनाने पर बल दिया।

फ्लैगशिप योजनाओं में प्रगति लाएं

बैठक में धान खरीदी की स्थिति, किसानों के पंजीयन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, मॉडल आंगनबाड़ी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, कर्मयोगी अभियान तथा अन्य प्रमुख योजनाओं की प्रगति की भी विस्तृत समीक्षा की गई।

इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य श्री नंदलाल राठौर, जिला पंचायत सीईओ श्री अविनाश भोई, अपर कलेक्टर श्री चित्रकांत चार्ली ठाकुर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय बसना सलखण्ड में मां महालक्ष्मी पूजन कार्यक्रम में हुए शामिल

बसना सलखण्ड में मां महालक्ष्मी पूजन कार्यक्रम में हुए शामिल

मुख्यमंत्री ने की ग्राम सलखंड में महतारी सदन बनाने की घोषणा

मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को संविधान दिवस की दी बधाई

रायपुर, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज महासमुंद जिले के बसना तहसील अंतर्गत ग्राम सलखण्ड में ग्रामीणों द्वारा आयोजित महालक्ष्मी देवी पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने मां लक्ष्मी से प्रार्थना करते हुए प्रदेशवासियों के सुख-समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। पूजन कार्यक्रम के दौरान पुजारियों द्वारा पारंपरिक मंत्रोच्चार किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री ने श्रद्धापूर्वक भाग लिया। इसके बाद उन्होंने ग्रामीणों से आत्मीय मुलाकात कर उनकी समस्याओं और स्थानीय विकास कार्यों की जानकारी ली। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या साय एवं रायपुर उत्तर विधायक श्री पुरंदर मिश्रा भी साथ थे।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने ग्राम सलखंड में महतारी सदन की बनाने की घोषणा की। साथ ही यहां एनीकेट निर्माण के लिए जल संसाधन विभाग को आवश्यक जानकारी जुटाकर प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए कहा कि आज पवित्र अगहन मास के अवसर पर मां महालक्ष्मी की पूजा में शामिल होकर हृदय से अत्यंत आनंद और सौभाग्य की अनुभूति हो रही है। बसना और सलखंड के ग्रामवासियों ने वर्षों से जिस भक्ति और परंपरा को जीवित रखा है, वह छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत का गौरवपूर्ण उदाहरण है।अगहन मास हमारे अंचल के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। यह मास अन्न, धन और समृद्धि का प्रतीक है। इसी समय नई फसल खेतों में लहलहाती है, और घर-परिवार में सम्पन्नता के द्वार खुलते हैं। मां महालक्ष्मी जीवन में केवल धन ही नहीं, बल्कि सुख, शांति, उत्तम स्वास्थ्य और सदभाव का आशीर्वाद भी प्रदान करती हैं। इसी भावना के साथ हम सभी इस पूजन में शामिल होते हैं। उन्होंने मां लक्ष्मी से राज्य के प्रत्येक नागरिक के लिए सुख-समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य, सुरक्षित वातावरण और उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार गांव, गरीब, किसान, महिला और युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। हम जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए संकल्पित हैं। सलखंड गांव की यह 25 वर्षों से चल रही परंपरा न केवल श्रद्धा का प्रतीक है, बल्कि सामाजिक एकता, भाईचारे और सामुदायिक जागरूकता का भी उदाहरण है। यहां आयोजित मेला ग्रामीण संस्कृति, लोकाचार और पारंपरिक विरासत को आगे बढ़ाने का माध्यम बन चुका है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने संविधान की गरिमा, लोकतांत्रिक मूल्यों और राष्ट्रनिर्माण में जनभागीदारी के महत्व को बताते हुए कहा कि संविधान हमारे अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों की भी याद दिलाता है और यही दस्तावेज भारत को एक सशक्त, एकजुट और प्रगतिशील राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ने की दिशा देता है। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ निर्माण समिति के सदस्यों के ऐतिहासिक योगदान का सम्मानपूर्वक उल्लेख किया और कहा कि समिति की दूरदृष्टि एवं प्रयासों ने आज के मजबूत और विकसित होते छत्तीसगढ़ की नींव रखी है।

माकड़ी ब्लॉक में 100 पीएम सूर्य घर का सफल इंस्टालेशन, कोण्डागांव जिला बन रहा सौर ऊर्जा का नया हब

रायपुर । सोलर उर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। कोंडागांव जिले का माकड़ी ब्लॉक आज पूरे बस्तर संभाग में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में एक नया केन्द्र बनकर उभर रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के हर घर सोलर विज़न को वास्तविक रूप देने वाली पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ने इस क्षेत्र में न केवल सुलभ ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित की है, बल्कि इससे ग्रामीण जीवन में बड़ा बदलाव आया है। डिस्ट्रिब्यूशन सेंटर मॉकडी ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत 100 घरों में रूफ्टॉप सोलर सिस्टम को सफ्लतापूर्वक ग्रिड से सिंक्रोनाइज करके एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की है, जो साबित करती है कि दूरस्थ और आदिवासी बहुल क्षेत्रों में भी सौर ऊर्जा अपनाने की जागरूकता तेजी से बढ़ रही है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत अब तक जिले में कुल 284 घरों में सोलर पैनल लग चुका है, जिसमें 50 से अधिक इंस्टॉलेशन सिर्फग्राम माकड़ी में ही किए गए हैं। उक्त योजना के तहत घरों की छतों पर स्थापित सोलर पैनल से घरेलू खपत की पूर्ति में सक्षम होते हैं और बिजली की अतिरिक्त उत्पादन से आय भी प्राप्त कर सकते हैं। इस पहल की सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्र और राज्य शासन की संयुक्त सब्सिडी ने ग्रामीण परिवारों के लिए सोलर सिस्टम लगवाना बेहद आसान कर दिया है।

संविधान में आस्था रखकर आगे बढ़ रहा है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत : मुख्यमंत्री साय

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय संविधान दिवस के अवसर पर आयोजित ÷हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान÷ कार्यक्रम में हुए शामिल

संविधान की प्रस्तावना का किया गया सामूहिक वाचन

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय आज 75वें संविधान दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर स्थित टाउन हॉल में आयोजित ÷हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान÷ कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री श्री साय ने उपस्थित जनसमूह के साथ संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन किया और संविधान के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने संविधान दिवस पर आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने संविधान पर आधारित लघु फिल्म भी देखी और जनप्रतिनिधियों के साथ इस अवसर को यादगार बनाने के लिए सेल्फी ली।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत सदैव संविधान में आस्था रखते हुए आगे बढ़ रहा है। संविधान प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता के साथ अपनी बात रखने का अधिकार देता है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। उन्होंने कहा कि विधायक और सांसद जैसे पदों पर आम नागरिकों का पहुँचना संविधान की ही उदार, समावेशी और लोकतांत्रिक व्यवस्था का परिणाम है। मुख्यमंत्री ने संविधान निर्मात्री सभा में देश के सभी क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के संविधान निर्माण अमूल्य योगदान दिया को स्मरण किया। उन्होंने विशेष रूप से छत्तीसगढ़ से भारत के संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले वरिष्ठजनों का स्मरण करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की यह ऐतिहासिक भागीदारी आज भी गर्व का विषय है और इन महान जनप्रतिनिधियों की विचारशीलता, लोकतांत्रिक मूल्य और राष्ट्रनिर्माण की दृष्टि सदैव प्रेरणा देती रहेगी। इस अवसर पर विधायक श्री राजेश मूणत, विधायक श्री पुरंदर मिश्रा, विधायक श्री सुनील सोनी, संस्कृति विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव सहित बड़ी संख्या में प्रबुद्धजन एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

तुंहर टोकन ऐप से किसान बन रहे हैं स्मार्ट, घर बैठे मिल रहा टोकन, समय और धन दोनों की बचत

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में धान खरीदी प्रक्रिया को डिजिटल और पारदर्शी बनाने के लिए लागू किया गया तुंहर टोकन ऐप किसानों के लिए बेहद उपयोगी साबित हो रहा है। इस ऐप के माध्यम से किसान अब बिना किसी परेशानी के घर बैठे ही धान विक्रय के लिए टोकन प्राप्त कर रहे हैं। इससे उपार्जन केंद्रों में लगने वाली लंबी कतारों से मुक्ति मिली है और समय के साथ-साथ श्रम की भी बचत हो रही है। सरगुजा जिले के ग्राम पंचायत रामपुर के किसान श्री सोहन राजवाड़े ने बताया कि उन्होंने मोबाइल फोन से तुंहर टोकन ऐप का उपयोग कर अपने पिता के नाम से धान विक्रय हेतु टोकन कटवाया। डिजिटल सुविधा के चलते उन्हें उपार्जन केंद्र के बार-बार चक्कर नहीं लगाने पड़े और पूरा काम आसानी से घर बैठे हो गया।

उन्होंने बताया कि उन्होंने 36 क्विंटल धान का टोकन ऑनलाइन प्राप्त किया। निर्धारित तिथि पर जब वे रामपुर धान उपार्जन केंद्र पहुंचे तो तुरंत बारदाना उपलब्ध कराया गया और नमी परीक्षण से लेकर तुलाई तक की पूरी प्रक्रिया बिना किसी बाधा के सुचारू रूप से संपन्न हुई।

श्री राजवाड़े ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की सरकार द्वारा धान का समर्थन मूल्य 31 रुपए प्रति किलो निर्धारित किए जाने से किसानों को आर्थिक लाभ मिल रहा है। साथ ही, जिला प्रशासन द्वारा बनाई गई पारदर्शी व व्यवस्थित खरीदी प्रणाली के लिए उन्होंने आभार व्यक्त किया।

डिजिटल व्यवस्था, विशेषकर तुंहर टोकन ऐप, प्रदेश में धान खरीदी को अधिक सरल, सुविधाजनक और किसान हितैषी बना रही है। आधुनिक तकनीक का लाभ उठाकर अब ग्रामीण क्षेत्रों के किसान भी स्मार्ट तरीक़े से अपने कार्य कर पा रहे हैं।

जिला खाद्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 26 नवंबर को कुल 559 किसानों ने टोकन कटवाया, जिनमें से 169 किसानों ने तुंहर टोकन ऐप के माध्यम से घर बैठे टोकन प्राप्त किया।

उपमुख्यमंत्री ने मतदान केंद्र पहुंचकर भरा अपना एसआईआर का फार्म, नागरिकों से विशेष गहन पुनरीक्षण में भाग लेने की अपील की

रायपुर। उपमुख्यमंत्री एवं कवर्धा विधायक श्री विजय शर्मा ने आज अपने कवर्धा प्रवास के दौरान मतदान केंद्र में जाकर अपना विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का फार्म भरा। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा कवर्धा के वार्ड क्रमांक 23 में स्थित मतदान केन्द्र क्रमांक 238 में पहुंचकर बीएलओ के साथ चर्चा कर अपना फॉर्म भरा। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों को एसआईआर के संबंध में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक और लोगों को हो रही समस्या के संबंध में जाना। उन्होंने फार्म में त्रुटियों के प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए समस्या का निराकरण करने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री ने विशेष गहन पुनरीक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने और मतदाता सूची के शुद्धिकरण के लिए चुनाव आयोग द्वारा कराई जाने वाली यह एक अत्यंत आवश्यक प्रक्रिया है। मतदाता सूची के सही होने से निर्वाचन प्रक्रिया उचित तरीके से सम्पन्न हो सकेगी। एसआईआर की प्रक्रिया कराने के लिए अपने बीएलओ से संपर्क कर फॉर्म भर सकते हैं या खुद भी ऑनलाइन आवेदन भरा जा सकता है। उन्होंने बीएलओ के साथ बैठकर आये आवेदनों पर समीक्षा भी की।

जिले के शासकीय कार्यालयों एवं स्कूलों में संविधान की प्रस्तावना का किया गया सामूहिक वाचन

जांजगीर-चांपा। 26 नवंबर संविधान दिवस के अवसर पर आज कलेक्टोरेट कार्यालय सहित विभिन्न शासकीय कार्यालयों एवं स्कूलों के छात्र-छात्राओं और विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक रूप से वाचन किया। कलेक्टोरेट सभाकक्ष में अधिकारी-कर्मचारियों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया और संविधान से संबंधित विभिन्न जानकारियां भी दी गई। 26 नवम्बर 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंगीकृत किया था। प्रति वर्ष 26 नवम्बर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान दिवस का उद्देश्य नागरिकों को संविधान की मूलभूत धारा और उद्देश्य से अवगत कराना है।

मतदाता सूची में बढ़ती गड़बड़ियों पर पूर्व विधायक विकास उपाध्याय और पूर्व मेयर एजाज़ ढेबर का चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप

रायपुर । विशेष गहन पुनरीक्षण (स्ढ्ढक्र) की प्रक्रिया तेज होते ही मतदाता सूची की खामियां लगातार सामने आ रही हैं। इस बढ़ती अव्यवस्था को लेकर पूर्व विधायक *विकास उपाध्याय* और पूर्व महापौर *एजाज़ ढेबर* ने चुनाव आयोग पर बिना तैयारी के स्ढ्ढक्र लागू करने का आरोप लगाया है। विकास उपाध्याय ने बताया कि रामसागर पारा की रामजी हलवाई गली के करीब 80 नागरिकों के नाम 2003 की मतदाता सूची से गायब पाए गए, जबकि ये लोग वर्षों से मतदान करते आ रहे हैं। उन्होंने निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात कर मामले की शिकायत की और कहा कि स्ढ्ढक्र को बिना ठोस तैयारी के लागू किया गया है, जिसके कारण आम नागरिक परेशान हो रहे हैं। उपाध्याय ने यह भी आरोप लगाया कि बीएलओ को जरूरी जानकारी नहीं दी गई है और लोगों से फॉर्म भरने को कहा जा रहा है, जबकि 2003 की मूल सूची ही उपलब्ध नहीं कराई जा रही। उनका कहना है कि यदि पहले बीएलओ और सुपरवाइजर को प्रशिक्षण दिया जाता और सभी दस्तावेज व्यवस्थित किए जाते, तो जनता को इस तरह भटकना नहीं पड़ता। इधर पूर्व महापौर *एजाज़ ढेबर* ने भी मतदाता सूची में हो रही भारी गड़बड़ियों को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही नहीं बल्कि नागरिकों के मतदान के संवैधानिक अधिकार पर सीधा असर डालने वाली स्थिति है। ढेबर ने आरोप लगाया कि 2003 से निरंतर मतदान कर रहे हजारों नागरिकों के नाम बिना किसी सूचना, कारण या सत्यापन के मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं, जो चौंकाने वाली और अस्वीकार्य चूक है। ज्ञापन में यह भी बताया गया कि कई नागरिकों ने ऑनलाइन और ऑफ्लाइन स्ढ्ढक्र फॉर्म भरे, लेकिन किसी को कोई रसीद या पावती नहीं मिली, जिससे आवेदन की स्थिति पता लगाना असंभव हो गया है। ढेबर ने इसे बेहद गंभीर बताया और कहा कि बिना पावती नागरिक यह साबित भी नहीं कर सकते कि उन्होंने आवेदन किया था।

स्वामी,मुद्रक,प्रकाशक प्रेमेन्द्र अग्रवाल द्वारा अस्मा पब्लिशर्स इण्डिया प्राईवेट लि.,जयस्तंभ चौक, रायपुर से मुद्रित कर तथा 5/756 रामसागरपारा, सिंधी स्कूल के पीछे, स्टेशनरी हाऊस, रायपुर 492001 (छ.ग.) से प्रकाशित। **संपादक प्रेमेन्द्र अग्रवाल ।**
www.lokshakti.in, lokshaktidaily@gmail.com, twitter.com/lokshaktidaily, facebook.com/lokshaktidaily **कार्यकारी संपादक : राजेश अग्रवाल** (किसी भी विवाद पर न्यायालय क्षेत्र रायपुर होगा)